कमल संदेश

ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल

विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : **100/-**

त्रि वार्षिक : **250/-**

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798

Qku (dk-) : +91(11) 23381428

QSD I : +91(11) 23387887

पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई-मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय-सूची

श्री राजनाथ सिंह का अध्यक्षीय उद्बोधन............ 6

राजनीतिक प्रस्ताव............ 19

आर्थिक प्रस्ताव............ 24

श्री नरेन्द्र मोदी का उद्बोधन............ 29

श्री लालकृष्ण आडवाणी का मार्गदर्शन............ 4

मुख पृष्ठ : *भाजपा राष्ट्रीय परिषद बैठक का शुभारम्भ करते वरिष्ठ नेतागण*

सूचना

18 एवं 19 जनवरी 2014 को रामलीला मैदान, दिल्ली में संपन्न भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए अध्यक्षीय भाषण का पूरा पाठ एवं पारित प्रस्तावों को एक पुस्तिका में अलग से प्रकाशित किया जा रहा है, जिसे भाजपा कार्यालय, पुस्तक विक्रय केंद्र, 11 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 से प्राप्त किया जा सकता है।

लक्ष्य हासिल करने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ें : लालकृष्ण आडवाणी

भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की दो दिवसीय बैठक में अपने मार्गदर्शन भाषण में भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि आजादी के बाद से यह 16वां चुनाव होगा, मैंने सभी चुनाव देखे हैं और अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, उनमें पार्टी में ऐसा उत्साह और आत्मविश्वास कभी नहीं देखने को मिला। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और सभी सदस्यों को बधाई देता हूं जिन्होंने यह तय किया कि चुनाव के बाद बहुमत आने पर श्री नरेन्द्र भाई हमारे प्रधानमंत्री होंगे और जिन्होंने 272 प्लस सीट प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया।

श्री आडवाणी ने कहा कि हमें इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी है। हमें इसे साध लेना है। हम जून के महीने में मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य लेकर चलें। उन्होंने कहा कि हम 2004 में चुनाव हार गए और इसका कारण अति आत्मविश्वास था। इस लोकसभा चुनाव में हमें सुनिश्चित करना है कि हम केवल विश्वास के साथ चुनाव लड़ें। श्री मोदी की प्रशंसा करते हुए श्री आडवाणी ने कहा कि बड़ा लक्ष्य हो तो महत्वाकांक्षा भी बड़ी होनी चाहिए। पिछले पांच-छह महीने से नरेन्द्र भाई के साथ पार्टी ने अभियान चलाया, बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया, किसी अन्य नेता ने लगातार ऐसे लोगों के सामने अपनी बात नहीं रखी। उन्होंने कहा कि आज भी श्री मोदी ने सुशासन के साथ इन्द्रधनुष की जो व्याख्या की, वह आने वाले वर्षों में पार्टी की सोच और दृष्टि को रेखांकित करती है।

श्री आडवाणी ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उस प्रदेश से उनका पहला परिचय 1943 में हुआ और तब उन्होंने गांधीजी के बारे में सुना। गांधीजी को साबरमती का संत कहा जाता था। लेकिन साबरमती नदी को देखकर उन्हें काफी दुख होता था जो एक गंदे नाले के समान थी। उन्होंने कहा, नरेन्द्रभाई अपनी अन्य उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं लेकिन जिस तरह से नर्मदा का पानी लाकर साबरमती नदी का कायाकल्प किया... यह वाकई गर्व की बात है। सुशासन देने और उसका सर्वाधिक लाभ गरीबों को हो, ऐसा काम उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने भारत के लिए वोट मांगा और जिन बातों पर मांगा, उसकी हर एक बात हमारी संस्कृति में निहित है। भाजपा ने पूरी दृष्टि और सोच देश के सामने रखी है। श्री आडवाणी ने लोगों से कहा कि आप किसी भी देवी की पूजा करते हों, आने वाले 50 वर्षों के लिए उन्हें सोने दें, और एक देवी की पूजा करें, उसे जागृत रखें वह देवी है भारत माता। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने 15वीं लोकसभा एक जून को गठित होने की बात कही है, हम यह सोच लेकर चलें कि जून महीने में श्री मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। ■

व्यंग्य चित्र

सम्पादकीय

देश में चाहिए मजबूत सरकार

2014 का लोकसभा चुनाव आसन्न है। ऐसे में हाल ही में संपन्न भारतीय जनता पार्टी की एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं दो दिवसीय राष्ट्रीय परिषद् बैठक स्वत: महत्वपूर्ण हो जाती है। भाजपा का विस्तार कैसे हो? जनाकांक्षा की पूर्ति कैसे हो? देश जो सोच रहा है, दल उस पर खरा कैसे उतरे? इस पर गहन चर्चा इन तीन दिवसीय बैठक में हुई। साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुए। इस बैठक में पार्टी के व्यापक विस्तार के लिए 'वन वोट, वन नोट', 'मिशन 272 प्लस' एवं 'मोदी फॉर पीएम फंड' अभियान के बारे में प्रतिनिधियों को विस्तार से बताया गया। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे जनता तक पहुंच सुनिश्चित की जाय, इससे भी सबको अवगत कराया गया।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का उद्घाटन करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केन्द्र की यूपीए सरकार पूरी तरह अकर्मण्य है। जनता यूपीए को आम चुनाव में उखाड़ फेंकेगी। कांग्रेस के सारे प्रयासों और हथकंडों के बावजूद देश में कांग्रेस के कुशासन, अनिर्णय और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता में जबरदस्त रोष है। हाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जनता का यह गुस्सा झेलना पड़ा है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि देश में कमजोर सरकार लाने का सपना देखने वाली ताकतों को भाजपा के कार्यकर्ता मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मिशन 2014 के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दें। उन्होंने जहां राष्ट्रीय संकट से देश और दल को अवगत कराया, वहीं यूपीए की असफलताओं पर जमकर प्रहार किया। पार्टी का विस्तार कैसे हो और हमारा गठबंधन और कैसे मजबूत हो, इससे जुड़े मसलों पर भी उन्होंने अपनी बात बेबाक रखी।

कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा भाजपा को सांप्रदायिक बताए जाने पर श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लोगों को भरमाने की कोशिश हो रही है। श्री सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था कि राष्ट्रीय संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला हक है। सेना में भी धार्मिक आधार पर पहचान की कोशिश की गई थी। कांग्रेस नेताओं ने हिंदू आतंकवाद का आरोप लगाकर बांटने की कोशिश की गई थी। इसलिए कांग्रेस है देश की सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी।

वहीं राष्ट्रीय परिषद् बैठक में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी ने ओजस्वी भाषण देते हुए सतरंगी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत एक इंद्रधनुष की तरह है, जिसमें परिवार व्यवस्था, कृषि, नारी, जल-जमीन-जंगल, युवा शक्ति, लोकतंत्र और ज्ञान समाहित है। विकास तभी हो सकता है जब हर हिस्से का संतुलन हो, लेकिन संप्रग सरकार के काल में सब कुछ दांव पर लगा था। भाजपा सरकार में आई तो इस इंद्रधनुष को गहरा किया जाएगा।

बैठक में भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली के अलावा पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी, श्री एम वेंकैया नायडू और श्री नितिन गडकरी ने भी अपने विचार रखे।

राजनैतिक तौर पर इस महत्वपूर्ण बैठक में भाजपा के एक-एक कार्यकर्ता के लिए जहां इस बात का संदेश है कि अब विराम का समय नहीं बल्कि अविराम होकर सतत् कार्य करते रहना सभी कार्यकर्ताओं का नैतिक धर्म हो गया है।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार सभी मोर्चे पर विफल रही है। एक दशक के दौरान महंगाई, भ्रष्टाचार, कर्ज का ब्याज और बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है। जनता त्राहिमाम कर रही है, ऐसे में भाजपा का दायित्व बढ़ जाता है कि वह जनता की तकलीफों को दूर करे और देश में 'मजबूत' सरकार बनाए।

एक तरफ जहां इस बैठक से पूरे देश में उत्साह का वातावरण बना है वहीं भाजपा कार्यकर्ता पूरे जोश एवं उमंग से भर गए हैं। हर घर तक इस बैठक का संदेश पहुंचाना भाजपा कार्यकर्ता की अब महती जिम्मेवारी है। आइए एक सशक्त, सुदृढ़ समृद्ध भारत का निर्माण करने में प्राण-प्रण से जुट जाएं। ■

देश बदलाव चाहता है : राजनाथ सिंह

भारतीय जनता पार्टी की एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 17 जनवरी 2014 को एनडीएमसी सेंटर, नई दिल्ली में एवं दो दिवसीय राष्ट्रीय परिषद् बैठक 18 एवं 19 जनवरी 2014 को दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में संपन्न हुई। इस बैठक को भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी, श्री वैंकैया नायडू एवं श्री नितिन गडकरी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पार्रिकर ने सम्बोधित किया। राष्ट्रीय परिषद् बैठक में सारगर्भित अध्यक्षीय भाषण देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश में कांग्रेस ने जो हालात पैदा कर दिये हैं, उससे देश के आम आदमी में एक गहरी हताशा, निराशा और कुंठा व्याप्त हो गई है। श्री सिंह ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि तमाम झंझावातों के बीच अंततः भाजपा देश को एक नई रोशनी देने में सफल होगी। प्रस्तुत है अध्यक्षीय भाषण के प्रमुख अंश :

पिछली राष्ट्रीय परिषद में हम सब इसी दिल्ली में लगभग दस माह पूर्व मिले थे। इस बीच गंगा में बहुत पानी बह चुका है। परंतु जल की यह धारा शांत और निर्विकार नहीं है। इन लहरों में परिवर्तन की बेचैनी साफ दिख रही है। देश के जनमानस में परिवर्तन की लहरें हिलोरें ले रही हैं। ये लहरें सिर्फ सत्ता परिवर्तन के निमित्त नहीं, बल्कि भारत की साख, संवैधानिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और जनसामान्य की आशाओं पर हो रहे वज्रपात से निपटने के लिए है।

बदलाव की आशा से जनसामान्य किस ओर देख रहा है इसकी झलक हमें हाल ही में संपन्न राज्य विधानसभा चुनावों में मिल चुकी है। हमने चारों राज्यों में शानदार सफलता हासिल की है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ में हमारी सत्ता में तीसरी बार वापसी हुई है जो अपने-आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके लिए मैं सहजता, सरलता और जनसेवा के प्रतीक मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई देता हूँ तो वहीं अत्यंत विषम परिस्थितियों में देश के दुर्गम क्षेत्रों में से एक छत्तीसगढ़ में लगातार कमल खिलाने वाले कर्मठता के प्रतीक मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को भी बधाई देता हूँ। साथ ही मैं इन प्रदेशों में पार्टी के समस्त कार्यकर्त्ताओं को बधाई देता हूँ, जिन्होंने अपने अथक प्रयत्न से यह इतिहास बनाने में भूमिका निभाई।

वहीं अपनी संघर्षशीलता, सांगठनिक कौशल एवं दक्ष प्रबंधन के द्वारा राजस्थान की मरुभूमि में कमल खिलने वाली श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया को भी बधाई देता हूँ और राजस्थान प्रदेश के समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं को इस अभूतपूर्व बहुमत के लिए भी बधाई देता हूँ।

दिल्ली में भी डॉ. हर्षवर्धन के नेतृत्व में हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे परंतु बहुमत से कुछ कदम के फासले पर रह गए।

मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनावी सफलता की चर्चा तो मैंने कर दी परन्तु हमें गुजरात और गोवा की भाजपा सरकारों के शानदार Performance को भी नहीं भूलना चाहिए। इन प्रदेशों की जनता श्री नरेन्द्र मोदी और श्री मनोहर पर्रीकर के नेतृत्व वाली सरकारों के कामकाज की प्रशंसा मुक्त कंठ से कर रही है।

मैं देश के वैज्ञानिकों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने स्वदेशी क्रायोजनिक इंजन का निर्माण करके, GSLV P-5 का सफल परीक्षण करके और मंगलयान के द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक नई छलांग लगाई है और भारतीयों के मन में व्याप्त निराशा के अंधकार में गौरव की अनुभूति का एक अवसर भी दिया है।

मित्रों, अब देश लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। वैसे तो देश में हर पांच वर्ष के बाद चुनाव आते हैं, परन्तु आगामी लोकसभा चुनाव अपने आप में देश के भविष्य का निर्धारण करने वाला एक निर्णायक चुनाव है। क्योंकि 2004 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने भारत को ऊंचाई के जिस मुकाम पर पहुँचाने का काम किया था, विगत दस वर्षो में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने उस सारे काम का मानो काम-तमाम कर दिया है। यह बहुत चिंताजनक बात इसलिए है, क्योंकि जब 21वीं सदी का पहला सवेरा भारत मे भाजपा नेतृत्व की सरकार में देखा था तो भारत आकाश में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा था। दुनिया की तमाम बडी बडी कम्पनियां और संस्थान भारत आने को लालायित थे रोजगार के करोड़ों अवसर सृजित हो रहे थे। सारे विश्व में भारत की प्रगति के लिए ''The Indian sucess story'' कहा जाता था।

आंतरिक पक्ष में देखें तो देश के आम आदमी को मंहगाई ने कुचल कर रख दिया है। भ्रष्टाचार ने स्वतंत्र भारत के इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड दिये है। भ्रष्टाचार तो पहले भी कई सरकारों में बहुत हुआ है। श्री नरसिंह राव की अल्पमत वाली कांग्रेस सरकार रही हो या श्री राजीव गांधी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार, इन सभी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। परन्तु वर्तमान यूपीए सरकार ने न सिर्फ भीषण भ्रष्टाचार किया बल्कि उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए निर्लज्जता की सीमाएं पार करते हुए न सिर्फ सरकारी तंत्र का दुरूपयोग किया बल्कि सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं को छिन्न-भिन्न करने का काम किया।

आज हालात पूरी तरह उलट गए हैं। दुनिया भर के निवेशकों और बडी बडी कम्पनियों मे भारत से बाहर जाने की होड़ लगी है। अत: अब यह कहा जा रहा है The Indian sucess story is over.

हम सभी जानते है कि जब तक आपने शुरूआत न की हो सम्भावनाएं बहुत दिखती है परन्तु जब शुरूआत होने के बाद यदि पतन का दौर आ जाये तो पूरी साख पर प्रश्न चिह्न लग जाता है। लोगों का आप की क्षमता पर विश्वास खत्म होने लग जाता है फिर उस खोए हुए विश्वास को पुन: पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत के साथ कुछ वैसा ही हो रहा है। इसलिए आगामी चुनाव यह तय करेगा कि भारत के प्रति दुनिया का खोया हुआ विश्वास वापस लौटेगा या नही? मैं यह मानता हूं कि भाजपा सत्ता में आएगी तो दुनिया का भारत में विश्वास पुन: लौटेगा। The Indian Success story is not over, it is waiting for BJP to come into Power.

आंतरिक पक्ष में देखें तो देश के आम आदमी को मंहगाई ने कुचल कर रख दिया है। भ्रष्टाचार ने स्वतंत्र भारत के इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड दिये है। भ्रष्टाचार तो पहले भी कई सरकारों में बहुत हुआ है। श्री नरसिंह राव की अल्पमत वाली कांग्रेस सरकार रही हो या श्री राजीव गांधी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार, इन सभी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। परन्तु वर्तमान यूपीए सरकार ने न सिर्फ भीषण भ्रष्टाचार किया बल्कि उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए निर्लज्जता की सीमाएं पार करते हुए न सिर्फ सरकारी तंत्र का दुरूपयोग किया बल्कि सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं को छिन्न-भिन्न करने का काम किया।

वैसे तो आप सभी को यह सारे प्रकरण याद होंगे फिर भी दो-तीन प्रमुख बिन्दु अवश्य हमारे ध्यान मे रहने चाहिए। इस सरकार ने अपनी स्थापना के साथ प्रधानमंत्री के पद और कैबिनेट की गरिमा को कम कर दिया। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री महोदय ने सत्ता के दो केन्द्रों की बात स्वीकार भी कर ली।

जुलाई 2010 में 2जी मामले पर जेपीसी बनाने के मुददे पर पूरा का पूरा मानसून सत्र सरकार की हठधर्मिता की भेंट चढ गया। अत: सरकार ने न्यायालय के हस्तक्षेप पर जेपीसी गठित की और जेपीसी की रिपोर्ट के साथ जो कुछ किया गया और वह पीएसी, जिसके सामने प्रधानमंत्री ने स्वयं उपस्थित होने की बात कही थी, उस पीएसी की रिपोर्ट को प्रस्तुत न होने देने के लिए कांग्रेस ने सपा और बसपा जैसे भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे दलों के साथ जो दुरभिसंधि की उसे सारे देश ने देखा। भारत के इतिहास मे इससे पहले कभी संसद और संसदीय कमेटियों की व्यवस्था को इस ढंग से धवस्त करने का प्रयास नही हुआ जैसा कि इस सरकार के समय हुआ।

कोयला घोटाला के विषय मे सीबीआई का दुरूपयोग, फिर सर्वोच्च न्यायालय मे गलत हल्फनामा और फिर न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर फाइलें खो जाना देश के इतिहास में अभूतपूर्व शर्मनाक घटना थी। भ्रष्टाचारियों को बचाने की इस निर्लज्जता से लेकर मंहगाई के विषय को लेकर मंत्रियों की असंवेदनशील टिप्पणियों तक जो कुछ भी घटित हुआ उसने आम आदमी का विश्वास पूरी की पूरी व्यवस्था पर से उठा दिया।

अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक परिस्थितियों के साथ साथ देश की सुरक्षा को लेकर सीमाओं पर और देश के अन्दर जो कुछ इन दस वर्षो में घटित हुआ है उसे देख कर कोई भी समझदार और राष्ट्रभक्त नागरिक विचलित हो जायेगा। विगत तीन चार वर्षो में चीन ने यहां

सैंकडों बार सीमा पर अतिक्रमण किया। जब-तब लद्दाख से लेकर अरूणाचल तक दादागिरी दिखाता रहा और भारत सरकार निरीह बनी रही और वहीं पाकिस्तान हमारे जवानों का सिर काट कर ले जाता रहा, उसके जश्न मनाने के वीडियो भी दिखे। भारत के आम आदमी का खून खौला, मगर भाजपा के अलावा किसी भी राजनैतिक दल का खून खौलता नजर नही आया।

आतंरिक सुरक्षा के मुददे पर देश के सभी गैर एनडीए राजनैतिक दल आतंकवाद के विरूद्ध कठोर कानून बनाने के हक मे नही हैं जबकि आतंकवाद की घटनाओं मे भारी बढ़ोतरी हुई है। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत दुनिया में आतंकवाद से सर्वाधिक पीडित देश है पर दुनिया का इकलौता देश है जोकि बगैर आतंकवाद विरोधी कानून के आतंकवाद से लड़ रहा है।

कहने का तात्पर्य यह है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से लेकर देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा तक, संवैधानिक व्यवस्थाओं के क्षरण से लेकर प्रंचड भ्रष्टाचार और मंहगाई तक ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त हो गई है। ऐसे मे आम आदमी का व्यवस्था पर से विश्वास उठना स्वाभाविक है।

हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा को शानदार सफलता हासिल हुई है और कांग्रेस लगभग लुप्तप्राय हो गई है। आगामी लोकसभा चुनावों मे कांग्रेस ने अपनी पराजय मन ही मन स्वीकार कर ली है। परन्तु कांग्रेस राजनीतिक की बहुत चतुर और चालाक खिलाड़ी है। हम सब ने देखा कि दस साल तक कांग्रेस ने सरकार मे एक मुखौटे की ओट लेकर पीछे से सारी शक्ति का संचालन और देश का दोहन किया। अब कांग्रेस की रणनीति यह है कि अगले चुनाव मे किसी भी प्रकार से भाजपा को बहुमत के नजदीक पहुचने से रोका जाये इसके लिए उसने कुछ और शक्तियों की ओट लेकर भाजपा के विरूद्ध दुष्प्रचार शुरू किया है।

मित्रों, देश के अंदर और बाहर की खतरनाक परिस्थितियों से निपटने के लिए और आम आदमी के कष्ट काटने और ध्वस्त हो रही संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए देश मे एक मजबूत सरकार चाहिए। परन्तु कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती। क्योंकि यदि भाजपा की मजबूत सरकार आ गई तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छतीसगढ़ की भांति शायद कांग्रेस के भविष्य पर ही प्रश्न चिह्न लग जाये। अत: भाजपा एक ''मजबूत'' सरकार चाहती है पर कांग्रेस एक ''मजबूर'' सरकार चाहती है ताकि 1977, 1989 और 1996 की भांति उस सरकार को एक-दो वर्षो मे अस्थिर करके सत्ता में वापसी की कोई जुगत बैठाई जा सके। आज देश बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी कहा है कि यदि देश मे एक कमजोर सरकार आई तो आर्थिक स्थिति और खराब हो सकती है। स्वाभाविक है कि मंहगाई और बेरोजगारी से निजात सिर्फ एक मजबूत सरकार ही दे सकती है और मजबूत सरकार आज की परिस्थिति में सिर्फ भाजपा ही दे सकती है।

मित्रों आप सभी 1977 से लेकर हाल मे सम्पन्न विधानसभा चुनावों तक देख चुके हैं। कांग्रेस का विकल्प सिर्फ और सिर्फ भाजपा है। भाजपा के अलावा किसी भी अन्य दल को दिया गया वोट, चाहे वह कांग्रेस विरोध की कितनी ही दुहाई दे रहा हो, कांग्रेस के विरूद्ध हमसे ज्यादा तीखी भाषा का प्रयोग कर रहा हो, कभी भी कांग्रेस से हाथ मिला सकता है। आज भारत की राजनीति मे एक युगांतर स्थापित हो रहा है। एक जमाना था जब कांग्रेस भारत की राजनीति के केन्द्र मे थी और शेष सभी दल कांग्रेस को रोकने के लिए प्रत्यक्ष या प्ररोक्ष रूप से सामूहिक प्रयास करते थे। आज युग बदल रहा है, आज कांग्रेस समेत देश के कुछ अवसरवादी दल भाजपा को रोकने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हाथ मिला रहे हैं। स्वाभाविक है कि भारत की राजनीति के केन्द्र मे अब भाजपा स्थापित हो चुकी है। अब भारत की राजनीति में कांग्रेस के युग का अंत और भाजपा युग का आरंभ हो चुका है। मैंने गत वर्ष दिल्ली की राष्ट्रीय परिषद मे यह कहा था भारत की राजनीति मे 20वी सदी कांग्रेस की थी अब 21वीं सदी भाजपा की होगी। एक वर्ष के घटनाक्रम ने देश की राजनीति के इसी दिशा मे बढ़ने के संकेत दिये है अत: कांग्रेस-मुक्त भारत के लिए एकमेव विकल्प भाजपा ही है।

मैं ईमानदारी से यह स्वीकार करता हूँ कि आज देश में कांग्रेस ने जो हालात पैदा कर दिये है उससे देश के आम आदमी मे एक गहरी हाताशा, निराशा और कुंठा व्याप्त हो गई है। परन्तु यह भी एक यथार्थ है कि किसी भी व्यक्ति के धैर्य, धर्म और विवेक की परीक्षा उसी समय होती है जब वह सर्वाधिक हताशा और कुंठा के समय मे हो। कांग्रेस पार्टी अपने कुछ सहयोगी दलों के द्वारा इस हताशा और कुंठा का प्रयोग देश को भाजपा नेतृत्व की मजबूत और सक्षम सरकार देने से रोकने के लिए कर रहे है। मैं देश की जनता से दो टूक कहना चाहूंगा कि यदि कांग्रेस की पीछे से लड़ाई लड़ने की रणनीति सफल हो गई तो देश मे एक अस्थिरता उत्पन्न होगी। देश और विदेश के उदाहरण ये प्रमाणित करते है कि ऐसी अस्थिरता मे से या तो कोई ऐसा नेतृत्व उभरेगा जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूब जायेगा, अथवा ऐसा नेतृत्व उभर सकता है जो वोट बैंक की राजनीति के लिए सारे सामाजिक तानेबाने को छिन्न-भिन्न करने लगेगा अथवा ऐसा नेतृत्व उभर सकता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खतरनाक समझौते करने लगेगा अथवा ऐसा नेतृत्व उभर सकता जो अपरिपक्वता और अपनी छवि बनाने के चक्कर मे लोकतंत्र को भीड़तंत्र मे बदलने लगे। हमे यह ध्यान रखना होगा कि ''लूट का बंटवारा'' करने वाले लोग तो जाने चाहिए परन्तु ''भानुमती का पिटारा'' लेकर सरकार चलाने वाले लोग भी नही आने चाहिए।

मुझे भारत की जनता की परिपक्वता और विवेक पर पूरा भरोसा है कि वह ऐसी किसी परिस्थिति को जन्म नहीं देगी बल्कि देश की सभी समस्याओं का समाधान करने मे समक्ष श्री नरेन्द्र मोदी

के नेतृत्व मे भाजपा को निर्णायक ताकत देगी। इन सारी समस्याओं का समाधान भाजपा के पास है।

इसका समाधान क्या है? इसका समाधान किसी एक मुद्दे मे नही, किसी एक तरीके मे नहीं बल्कि एक बहु-आयामी क्षमता के साथ एक जांचे, परखे और खरे नेतृत्व के द्वारा हो सकता है जो देश को चार चीजे दे सकें।

1. सुशासन 2. विकास 3. स्थिरता 4. सुरक्षा

परन्तु आज के भारत की स्थिति इसके सर्वथा विपरीत है।

भारतीय अर्थव्यवस्था :

विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का 'संक्रमण काल' से गुजरना कोई बहुत अस्वाभाविक बात नहीं है। परन्तु जब कोई सरकार लगातार गलत आर्थिक नीतियों पर गलत नीयत के साथ चलती रहे तो अर्थव्यवस्था का यह 'संक्रमण' एक गंभीर 'संक्रामक रोग' में परिवर्तित हो जाता है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस रोग का कारण सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनैतिक है।

एन.डी.ए. सरकार के समय 8 फीसदी से भी अधिक गति से घूमने वाला देश के विकास का पहिया आज यू.पी.ए. शासन में 5 फीसदी से नीचे की सुस्त रतार पर आ गया है। आर्थिक सुस्ती के संकेत यू.पी.ए. सरकार के दुबारा सत्ता सम्भालने के बार से ही प्रारम्भ हो गये थे मगर पांच साल बीतने को हैं सरकार सिर्फ 'कागजी घोड़े' दौड़ाती रही और हवाई घोषणायें करती रही।

आज जब विश्व की लगभग सभी बड़ी अर्थव्यवस्थायें 'Revive' कर रही हैं, वहां भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने अभी भी 'Survive' करने का संकट मुँह बाये खड़ा है। पिछले हफ्ते जो आर्थिक आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं उसको देखते हुए इस बात की चिंता होती है कि महीने दर महीने जब आर्थिक आंकड़े एक निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं तो कम से कम एक 'अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री' के अन्दर कुछ कर दिखाने की तड़पन क्यों नहीं दिखाई देती?

पिछले हफ्ते नवम्बर माह के 'IIP आंकड़े' जारी किए गये और हमें जानकारी प्राप्त हुई कि इस महीने में भी औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के बजाय 2.1 फीसदी की दर से घट गया है। यह सिर्फ एक महीने की बात नहीं है। अप्रैल 2013 से यदि हम हर महीने के औद्योगिक उत्पादन का औसत निकालें तो देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने की अपेक्षा लगातार घटा है।

जब विश्वव्यापी मंदी 2008-09 में छाई थी तो भी भारत की अर्थव्यवस्था तबाह नहीं हुई क्योंकि यहाँ की 'घरेलू मांग' ने विकास के पहिए को थामें रखा। यू.पी.ए. सरकार ने अर्थव्यवस्था की इस मजबूती का लाभ उठाने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना बेहतर समझा और अब जो आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं उसमें यह साफ पता चलने लगा है कि 'Domestic Demand' भी अब घटने लगी है। औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों में Consumer Non Durables के उत्पादन में आई 22 फीसदी की तेज गिरावट इशारा कर रही है कि भारतीय उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति घट रही है।

यू.पी.ए. सरकार समझती है कि बाजार में money supply बढ़ने से यह मांग में वृद्धि कर सकती है। यदि सिर्फ पैसे की आमद से ही बाजारों और अर्थव्यवस्था में रौनक आनी होती तो भारत में विकास की दर में गिरावट आने की बजाय वृद्धि होती। आंकड़े बताते है कि वर्ष 2006 में भारत में कुल मुद्रा आपूर्ति या money supply महज 25000 अरब रुपये थी जो दिसम्बर 2013 आते-आते बढ़ कर लगभग चार गुना यानि 92000 अरब रुपये हो चुकी है। इसके बावजूद न तो बाजार में मांग बढ़ी है और न ही देश की विकास दर में वृद्धि हुई है।

मुद्रा आपूर्ति में हुई इस वृद्धि ने यदि किसी चीज को बढ़ाया है तो वह महंगाई और भ्रष्टाचार को और इसे बढ़ावा देने में यदि किसी का हाथ है तो वह कांग्रेस नेतृत्व की यू.पी.ए. सरकार का है। अर्थव्यवस्था के नियम कहते हैं कि महंगाई एक मौद्रिक समस्या है जो मांग और आपूर्ति से प्रभावित होती है। लेकिन भारत में महंगाई एक राजनैतिक समस्या है जो कांग्रेस सरकार की देन है।

भारत की मौजूदा महंगाई के तार कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार से सीधे जुड़े हैं। अभी हाल ही में टर्की के कुछ अर्थशास्त्रियों ने एक अनूठा शोध किया है जिसके माध्यम से महंगाई और भ्रष्टाचार के संबंध का पता चलता है। इन अर्थशास्त्रियों ने Transparency International के आंकडों तथा मंहगाई के आंकडों का तुलनात्मक अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है कि भ्रष्टाचार का महंगाई पर भारी असर पड़ता है। वर्ष 2006 में Transparency International के मुताबिक भारत की पारदर्शिता रैंकिंग 70 थी जो अब 94 पहुंच गई है। यही वह कालखण्ड है जब मंहगाई ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना पूरा कब्जा जमाने में सफलता पाई है। मंहगाई देश की जनता को सीधे-सीधे प्रभावित कर रही है फिर भी यू.पी.ए. शासनकाल में मंहगाई के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाही नहीं हुई।

यू.पी.ए. सरकार का आर्थिक प्रबंधन भी बेहद निराशाजनक रहा है। इसकी झलक पहले हमें भारत के बढ़ते Current Account Deficit में मिली जो एक समय 90 बिलियन डालर से अधिक पहुँच गया था। यू.पी.ए. सरकार के बढ़ते Current Account Deficit ने भारतीय रुपये की कमर तोड़ दी और उसे डालर के मुकाबले बहुत जल्द सीनियर सिटिजन की श्रेणी में पहुंचा दिया। डालर के मुकाबले रुपये में आई गिरावट से निर्यात को जो बढ़ावा मिलना चाहिए था वह भी प्राप्त नहीं हुआ है।

सरकार यह दावा कर रही है कि इस वित्त वर्ष में चालू खाता घाटे को 60 बिलियन डालर तक सीमित रखा जायेगा मगर जिस तरह से सरकार अपने ही दावों को झुठलाती रही है उसे देखते हुए इस सरकार के किसी भी दावे पर यकीन करना मुश्किल है।

पिछले साल बजट प्रस्तुत करते समय वित्तमंत्री ने दावा किया था कि वित्त वर्ष 2013-14 में वित्तीय घाटे (Fiscal Deficit) को 5.42 लाख करोड़ से अधिक नहीं बढ़ने दिया जायेगा। जबकि हालत यह है कि नवम्बर 2013 में ही वित्तीय घाटे के बजट अनुमानों का 94 फीसदी हिस्सा खर्च हो चुका है और अभी चार महीनों का सरकार का हिसाब किताब बाकी है।

हाल ही में केन्द्र सरकार ने विदेशी कर्ज के जो आंकड़े जारी किए हैं वह और भी भयावह तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। मार्च 2013 को भारत का कुल विदेशी कर्ज 390 बिलियन डालर था जो सितम्बर 2013 में बढ़कर 400 बिलियन डालर को पार कर गया है। विदेशी कर्ज के भुगतान के लिए भारत का मौजूदा विदेशी मुद्रा भण्डार लगातार सिकुड़ता जा रहा है।

भारत के बढ़ते विदेशी कर्ज ने अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत की साख घटायी है। आज प्रमुख विकासशील देशों में भारत का विदेशी कर्ज का बोझ सर्वाधिक है। जहाँ फिलीपींस, इंडोनेशिया और टर्की जैसे देशों का Debt to GDP Ratio पचास फीसदी से भी नीचे है वहां भारत का Debt to GDP ratio लगभग सत्तर फीसदी (67.9%) है। इन परिस्थतियों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजंसियाँ जैसे 'मूडीज' भारत की कर्ज अदायगी की क्षमता पर संदेह जता रही हैं।

भारत की सुस्त विकास दर, ताबड़तोड़ मंहगाई और केन्द्र की निर्णय प्रक्रिया में विलम्ब के कारण देशी-विदेशी निवेशकों का भारत से मोह भंग हो रहा है। भारत सरकार के खुद के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। मौजूदा वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में FDI में 15 फीसदी की गिरावट हुई है।

यू.पी.ए. सरकार FDI को आकर्षित करने के लिए बिना सोच विचार किए एक के बाद एक क्षेत्र खोलती जा रही है। हाल ही में केन्द्र सरकार ने Railways को FDI के लिए खोल दिया जबकि यह एक सरकारी उपक्रम है। आर्थिक नीतियों को तय करते समय संसद और विपक्ष को विश्वास में लिया जाना चाहिए मगर केन्द्र सरकार द्वारा मनमानी की जा रही है। यही मनमाना रवैया विनिवेश के मामलों में भी दिखाया जा रहा है। इससे अनिश्चितता बढ़ती है। बजट के दौरान सरकार ने 44000 करोड़ का विनिवेश लक्ष्य रखा था मगर वह बमुश्किल 3000 करोड़ ही जुटा पाई है।

देश की अर्थव्यवस्था को पुनः रास्ते पर लाने का संकल्प भाजपा को लेना होगा। चूंकि अगले तीन-चार महीनों में लोकसभा चुनाव होने हैं इसलिए हमें इस देश के सामने एक स्पष्ट और प्रभावी 'दृष्टि पत्र' और 'संकल्प पत्र' रखना होगा जिसमें इस देश की Economy को Revive करने वाले महत्वपूर्ण सुझाव हो।

आज जनता यह जानना चाहती है कि सत्ता में आने पर हम देश की अर्थव्यवस्था को कैसे गति देंगे ? इसलिए इस राष्ट्रीय परिषद में आये सभी प्रतिनिधियों का यह दायित्व बनता है कि हम सब देश की इन समस्याओं की ही चर्चा न करें बल्कि उनके समाधान के जो सुझाव यहां दिये जायेंगे उनकी भी चर्चा आम जनता के मध्य करें। ताकि भाजपा के पास क्या समाधान है इससे भी आम जनता अवगत हो सके।

भाजपा विकास के मौजूदा आर्थिक मॉडल में काफी खामियां देखती हैं। हमारा यह मानना है कि विकास की मौजूदा रफ्तार और प्रसार इस देश के बहुत बड़े वर्ग को पीछे छोड़ देती है। आज देश में दूरियां बढ़ी हैं, आर्थिक विषमतायें बढ़ी है और देश की आर्थिक स्वायत्तता घटी हैं। इन परिस्थितियों में भाजपा को ऐसी आर्थिक नीतियां लागू करनी होगी जो दूरियां मिटायें, विषमताओं को समाप्त करें, उद्यम और उद्योग को बढ़ावा दे, किसानों का हित लाभ करें और देश के करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करें।

यह काम आसान नहीं है, मगर यह भी सच है कि यह काम केवल भाजपा के आर्थिक दर्शन और उसके नेतृत्व द्वारा ही सम्भव है। आर्थिक विकास के लिए सत्ता में आने पर Infrastructure Development यानि आधारभूत संरचना का विकास हमारा मुख्य ध्येय होगा।

यदि हमें बड़ा और महान देश बनाना है तो उसका ढांचा भी बड़ा बनाना होगा। अटलजी ने इस देश में पहले 'Infrastructure Revolution' का नेतृत्व किया था। उस समय देश का जल-भूतल परिवहन मंत्री होने के कारण अटल जी की इस महान परियोजना के श्रीगणेश का सौभाग्य मुझे मिला था और मुझे अटल जी की उस विराट दृष्टि को नजदीक से देखने का मौका मिला था। वह मिशन अभी अधूरा है। उसे पूरा करने की यह महती जिम्मेदारी अब हमारे भावी प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी निभायेंगे। हमारी सरकार का प्रयास होगा कि अगले पांच वर्षों में GDP के अनुपात में infrastructure में निवेश दुगुना किया जा सके।

शासन में आने पर भाजपा बेकाबू हो रहे Current Account Deficit और Fiscal Deficit को नियंत्रित करेगी। अटलजी के शासन काल में भारत Current Account Surplus वाली अर्थव्यवस्था बन गई थी। हम पुनः भारत को Current Account Deficit अर्थव्यवस्था की जगह Current Account Surplus अर्थव्यवस्था बनायेंगे। चालू खाता घाटा कम करने के लिए हम निर्यात को बढ़ावा देंगे। अनावश्यक विदेशी आयात को घटाने और भारतीय वस्तुओं के निर्माण और निर्यात को बढ़ाने के लिए समेकित योजना सरकार बनने के साथ ही हम लायेंगे।

विकसित देश की श्रेणी में आने के लिए हमें देश में 'Manufacturing' को बढ़ावा देना होगा। हमारे पास सस्ता और कुशल श्रम है फिर भी हम उसकी उपलब्धता का लाभ नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि देश में निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने की इच्छा शक्ति मौजूदा सरकार में नहीं है। हमारा लक्ष्य होगा कि देश की GDP में Manufacturing का हिस्सा बढ़ा कर 20 फीसदी में अधिक

कर दें।

इस देश की आधारभूत संरचना के निर्माण में सिर्फ देश के ही संसाधनों का ही नहीं बल्कि विदेश में भी मौजूद बड़ी संख्या में अनिवासी भारतीयों का भी हम सहयोग लेंगे। चीन के आर्थिक विकास की गाथा चीन की जनता के साथ-साथ विदेशों में बसने वाले चीनी मूल के लोगों ने भी लिया था।

भारत के Infrastructure में निवेश करने के लिए धन जुटाने के लिए देश में एक विकसित 'Bond Market' की जरुरत है जहाँ विभिन्न संस्थायें और एजेंसियाँ आधारभूत संरचना के विकास के लिए धन जुटा सकेंगी।

भारत में बढ़ते शहरीकरण और शहरों पर बढ़ रहे दबाव की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भाजपा एक नया 'Urban Renewal Plan' बनायेगी जिससे हमारे देश के सभी नगरों की क्षमता और संभावनाओं का पूरा विकास हो सके।

किसी भी सरकार की असली परीक्षा उसकी निर्णय क्षमता, पारदर्शिता और तत्परता से होती है। इसके अभाव में आर्थिक प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। यू.पी.ए. सरकार का उदाहरण हमारे सामने है जिसके कारण देश में project clearance में विलम्ब, संसाधनों का अनुचित प्रयोग, भ्रष्टाचार और project की कीमतें बढ़ने जैसी समस्यायें आई। भाजपा इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए पर्यावरण, औद्योगिक विकास और भूमि से संबंधित मामलों के तुरन्त निस्तारण की व्यवस्था देगी।

करों का सरलीकरण एवं राहत :

भारत में आम आदमी टैक्स के बोझ के तले दबा हुआ है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर सरकार ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर न लगा रखा हो। भाजपा सिद्धान्त रुप से इस बात सहमत है कि आम आदमी से टैक्स का बोझ कम होना चाहिए।

सरकार बनने पर हम ईमानदारी से टैक्स भरने वाले भारतीयों के लिए टैक्स का बोझ और उलझनें दोनों कम करने का प्रयास करेंगे। हम टैक्स ढांचे में व्यापक परिवर्तन करेंगे ताकि यह व्यावहारिक हो सके, सरकार को राजस्व और करदाताओं के लिए सुविधा बढ़ सके। आयकर देने वाले वेतनभोगी मध्य वर्ग को अच्छी खासी राहत देने के लिए भाजपा संकल्पबद्ध है।

काले धन की समस्या :

विगत लम्बे समय से भ्रष्टचार के चलते देश की पूँजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा काले धन के रुप में बदल गया है और विदेशी बैंकों में जमा है। इस विषय को सर्वप्रथम 2009 के लोकसभा चुनावों से पहले आदरणीय अडवाणी जी ने उठाया था और यह कहा था कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने की व्यवस्था करेंगे। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि इस विषय को राजनैतिक क्षेत्र के बाहर भी बाबा रामदेव एवं श्री अण्णा हजारे जैसे कई गणमान्य महानुभावों ने भी अपना मुखर समर्थन दिया है। हम आज भी आडवाणी जी के उस संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध हैं। यदि हमारी सरकार बनी तो हम विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लायेंगे।

कृषि और किसान :

कृषि और किसान के प्रति हमारा दृष्टिकोण जनसंघ के जमाने से ही स्पष्ट रहा है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी कहा करते थे हमारा लक्ष्य है 'हर खेत को पानी, हर हाथ को काम'। भाजपा भी जनसंध की उसी नीति का पालन कर रही है।

मौजूदा सरकार की नीतियां किसान विरोधी है। हाल ही में देश के कई राज्यों में गन्ना किसान आन्दोलित हुए है क्योंकि उन्हें अपनी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। मैं उ.प्र. का उदाहरण यहां देना चाहूंगा वहां किसान को प्रदेश सरकार प्रति क्विंटल गन्ने का समर्थन मूल्य मात्र 280 रूपये दिया है। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान आन्दोलन कर रहे हैं परन्तु उन्हें लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके लिए सरकार को एक व्यावहारिक फार्मूला तत्काल खोजना चाहिए।

मैं स्वयं किसान परिवार से हूं और किसान का दर्द मैं बखूबी समझता हूं। उसकी समस्या का सबसे बड़ा कारण कम आय और उस कम आय की भी अनिश्चितता है। यदि हमारी सरकार बनी तो हम किसानों के लिए - खेत के अनुसार किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए कृषि आय बीमा योजना लागू करेंगे।

हर किसान परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को वैकल्पिक रोजगार का एक अवसर अवश्य उपलब्ध करायेंगे।

सारे विश्व में लगातार लोकप्रिय हो रही जैविक खेती जोकि परंपरागत भारतीय खेती का एक हिस्सा है उसके प्रचार प्रसार के लिए विशेष कार्यदल बनायेंगे।

विश्व व्यापार संगठन एवं खाद्य सुरक्षा :

हाल ही मे बाली में WTO की मीटिंग में भले ही खाघ सुरक्षा को लेकर आने वाली मुसीबतो को थोड़ी देर के लिए टाल दिया हो मगर भारत की खाद्य सुरक्षा पर संकट के बादल अभी भी मंडरा रहे है। बाली में सरकार ने भारत को सब्सिडी के मामले में WTO के प्रावधानों का सामना करने से तब तक ही बचाया है जब तक सब्सिडी का कोई permanent solution नही निकलता। केन्द्र सरकार को चाहिए था कि वह इस समस्या का permanent solution निकालती क्योंकि कृषि पर WTO का 10 फीसदी सब्सिडी का जो प्रावधान है वह पहले ही पार हो चुका है। इसका असर किसानों को मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पडेगा क्योंकि 10 फीसदी की तुलना में 24 फीसदी की वृद्धि पहले ही हो चुकी है।

यदि कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य नही बढ़ाये जा सकेंगे और Input Cost बढ़ता रहेगा तो किसान किसानी कैसे करेगा? क्यों नही बाली में ही यू0पी0ए सरकार न इस मद्दे पर WTO को

अपना नजरिया स्पष्ट किया?

दरअसल यू0पी0ए सरकार ने WTO में अपने देश के किसानों के भविष्य के लिए संघर्ष नही किया सिर्फ समस्या को चुनावी वर्ष देखकर कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। अब समय आ गया है कि देश मे किसान हितैषी सरकारें ही सत्ता शासन की बागडोर सम्भालें और यह काम केवल भाजपा ही कर सकती है।

किसान बाजार :

किसानों को उनकी उपज के बेहतर मूल्य दिलाने के लिए पूरे देश मे 'किसान बाजार' को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि उपभोक्ता और किसान के बीच मे बिचौलियों को समाप्त किया जा सके। जो प्याज दीपावली के समय इतनी ऊंची कीमतों पर बिका कि आम आदमी परेशान हो गया परन्तु किसान को तो उसका 10 प्रतिशत भी नहीं मिला। यदि 'किसान बाजार' जैसी सीधी क्रय-विक्रय की व्यवस्था हो तो उपभोक्ता और किसान दोनों को लाभ होगा। पहले देश के हर शहर में सब्जी बाजार लगते थे, साप्ताहिक हाट लगती थी जहां किसान सीधा उपभोक्ता को सामान बेचता था।

आधुनिकता और व्यापारी हितों के दबाव मे साप्ताहिक बाजारें, सब्जी बाजारें और हाट क्रमशः समाप्त होती जा रही हैं। अब इक्कीसवी शताब्दी में 'किसान बाजार' हर नगर और कस्बे में चलाने की जरूरत है क्योंकि organized retail से न तो किसानों को लाभ होगा और न ही उपभोक्ताओं को।

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमरीका जैसे देश जहॉ वालमार्ट का कब्जा है वहॉ भी 'किसान बाजारों' की स्थापना का चलन लगातार बढ रहा है। 1970 मे जहां पूरे अमरीका मे मात्र 370 किसान बाजार थे वहां आज उनकी संख्या 2010 के आंकड़ों के मुताबिक 7000 किसान बाजारों से अधिक हो चुकी है। आस्ट्रेलिया मे 1999 में एक भी किसान बाजार नहीं था वहां आज 150 किसान बाजार है। अमेरिका मे किसान बाजारों के माध्यम में 1 लाख 36 हजार किसान सीधे उपभोक्तओं को अपनी उपज और उत्पाद बेच रहे हैं।

भाजपा सत्ता मे आने पर पूरे देश मे 'किसान बाजारों' को बढावा देगी जहॉ किसान सीधे अपना उत्पाद उपभोक्ताओं को बेच सकेगा। इससे किसानों को बेहतर दाम और उपभोक्ताओं को सस्ता माल मिलेगा और खाद्य वस्तुओं की जो महंगाई पिछले कई वर्षों से आम आदमी की कमर तोड़ रही है उससे निजात मिल सकेगी।

जनस्वास्थ्य :

किसी भी राज्य में आम आदमी के लिए चार चीजें सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व होता है। सुरक्षा, न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य। भारत के पिछड़े और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मानकों से बहुत कमजोर है। जबकि अच्छी स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा प्राप्त करना हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए। हम देश के हर गरीब नागरिक के लिए स्वास्थ्य का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान करेंगे।

आर्थिक विषमता :

भारत में विगत 10 वर्षों में एक बहुत बड़ी समस्या जिसके भविष्य में सामाजिक दृष्टि से खतरनाक परिणाम हो सकते हैं वह है आर्थिक विषमता। समाज के एक वर्ग का उत्तरोत्तर साधन सम्पन्न होते जाना और एक वर्ग का मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित रहना एक बहुत चिंताजनक स्थिति है। हम अपनी सरकार आने पर आर्थिक संसाधनों के सर्वस्पर्शी वितरण को सुनिश्चित करेंगे।

गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले करोड़ों लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य का दायित्व है। हमारी सरकार इस वर्ग को सरकारी सहायता का मोहताज न रखते हुए इन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए एक व्यापक रोजगार योजना बनायेंगे। हम बीपीएल समूह के लिए एक विशेष रोजगार योजना बनायेंगे, ताकि गरीब का हाथ बेबसी के साथ अनुदान मांगने के लिए उठने की आवश्यकता न रहे बल्कि आत्मविश्वास के साथ काम करने के लिए उठने योग्य बन सके।

यू.पी.ए. सरकार का भ्रष्टाचार :

केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार के भ्रष्टाचार से पूरे देश की जनता पीड़ित है। साढ़े पांच लाख करोड़ रुपये से भी अधिक के घोटालों को अंजाम देने वाली यह सरकार भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के नाम पर उन पर परदा डालने का काम कर रही है।

बहुचर्चित 2जी घोटाले में गठित संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में विपक्ष के नेताओं द्वारा जो लिखित 'Note of Dissent' दिये गये उन्हें संपादित करके एक अनुकूल रिपोर्ट बनाई गई। इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि जिन मुद्दों को आधार बनाकर यह J.P.C. गठित की गई थी उन पर कोई निर्णय देने के बजाय उसकी रिपोर्ट उन सवालों से बचकर निकल जाती है। भ्रष्टाचार के मामलों को ढकने के लिए लोकतन्त्र की संस्थाओं और परम्पराओं का ऐसा खुला दुरुपयोग शायद ही कहीं देखने को मिले।

इसी तरह मुम्बई में 'आदर्श हाऊसिंग सोसायटी' घोटाले की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस के इशारे पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा खारिज कर दी गई क्योंकि उसके एक दो नहीं चार-चार भूतपूर्व मुख्यमंत्री इस घोटाले में आरोपित थे। महाराष्ट्र सरकार ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दो घण्टे पहले ही कैबिनेट की बैठक कर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। भ्रष्टाचार के मामले को दबाने का ऐसा उतावलापन संदेह को पक्का करता है। और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा जैसी हास्यास्पद पुनर्समीक्षा की गई उससे यह साफ हो गया कि महाराष्ट्र सरकार से लेकर कांग्रेस के युवा उपाध्यक्ष तक सब महज एक नाटक खेल रहे थे।

कोयला घोटाला जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय की सीधी संलिप्तता थी उसकी जांच में जो फाइलें अहम हैं उनमें से कई फाइलें 'अदृश्य'

हो गई है। 'अदृश्य' इसलिए क्योंकि यू.पी.ए. सरकार यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि गायब हुई फाइलें वास्तव में गायब कर दी गई हैं। चूंकि गायब फाइलों का 'अदृश्य' होना सामान्य घटना नहीं है अब प्रधानमंत्री को ही सामने आना चाहिए। आखिर मामला सीधा उनसे जुड़ा हुआ है। फाइलों के गायब होने और प्रधानमंत्री की चुप्पी से कोयला घोटाले पर से पर्दा नहीं उठ पा रहा है।

कोयला घोटाले में प्रधानमंत्री के 'मौनव्रत' ने देश को सिर्फ 1.86 लाख करोड़ रुपये का नुकसान ही नहीं कराया है बल्कि उनकी चुप्पी के कारण देश में कोयला खनन की प्रक्रिया बाधित हुई है। इसके कारण देश को हर साल लाखों टन कोयला महंगी दर पर विदेशों से आयात करना पड़ रहा है। जबकि भारत के पास कोयले के इतने भण्डार हैं कि 200 वर्ष तक हमें कोयला आयात करने की आवश्यकता नहीं पडेगा।

देश की बहुमूल्य प्राकृतिक सम्पदाओं को कांग्रेस सरकार ने बहुत भ्रष्ट तरीके से लूटा है। भविष्य में इसे रोकने के लिए हमारी सरकार प्राकृतिक सम्पदाओं के उपयोग और आवंटन के लिए एक सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी नीति बनायेगी।

लोकपाल और कांग्रेस का पाखण्ड :

संसद के शीतकालीन सत्र में बरसों से प्रतीक्षारत 'लोकपाल विधेयक' चर्चा के बाद पारित हो गया। भारतीय संसदीय इतिहास की यह ऐतिहासिक घटना थी मगर जिस तरीके से कांग्रेस द्वारा 'लोकपाल' पारित कराने का श्रेय लेने की कोशिश हुई वह मर्यादा के अनुकूल नहीं था। लोकपाल को पारित कराने का प्रयास अटलजी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने भी किया था। वह अटलजी ही थे जिन्होंने अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा कि प्रधानमंत्री पर को भी लोकपाल के दायरे में लाया जाना चाहिए।

भारत में लोकपाल विधेयक पारित कराने के लिए एक बड़ा सामाजिक आन्दोलन हुआ जिसका नेतृत्व सुप्रसिद्ध समाजसेवी अण्णा हजारे ने किया। यदि लोकपाल बिल पारित होने का श्रेय किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है जो वह अण्णा हजारे को दिया जा सकता है और यदि किसी संस्था को दिया जाना चाहिए तो वह इस देश में लोकतंत्र का मन्दिर माने जानी वाली 'भारतीय संसद' को दिया जाना चाहिए। एक जिम्मेदारी विपक्षी दल के रुप में भाजपा ने 'लोकपाल बिल' पारित कराने में सरकार को पूरा समर्थन दिया मगर भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस जो पाखण्ड रहा है वह काफी हास्यास्पद और मर्यादाओं के प्रतिकूल है।

भाजपा का यह मत है कि खाली 'लोकपाल विधेयक' पारित हो जाने भर से देश में भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई में लोकपाल सिर्फ एक अंग है। यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में वातावरण बनाना है तो देश में कई और विधेयक पारित कराने की आवश्यकता है जिनमें Goods services Gaurantee Bill, Whistleblower Protection Bill, Protection of Corruption (Amendement) Bill इत्यादि प्रमुख है।

लोकपाल के प्रति भाजपा सिर्फ बयानबाजी नहीं करती बल्कि ठोस कार्य करती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि देश में जनलोकपाल लाने वाली यदि कोई पहली राज्य सरकार थी तो वह जनरल खण्डूड़ी के नेतृत्व वाली उत्तराखण्ड की भाजपा सरकार थी।

आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा :

यू.पी.ए. शासनकाल में देश की आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा का ताना बाना बिखर गया है। पटना में मुख्य प्रतिपक्षी राजनीतिक दल द्वारा आयोजित रैली में बम विस्फोट की घटना हो जाना यह साबित करती है कि न तो केन्द्र सरकार ने और न ही बिहार की प्रदेश सरकार ने आतंकवादियों से मिल रही चुनौतियों को गम्भीरतापूर्वक लिया है।

चूँकि राज्य कानून एवं व्यवस्था बरकरार रखने के लिए जिम्मेदार है और आतंकवाद एक राष्ट्रव्यापी समस्या है इसलिए इस समस्या का निदान किसी एक राज्य की क्षमता के बाहर हैं। इसके बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा इस परिस्थिति की संवेदनशीलता को समझते हुए कोई राष्ट्रीय नीति या योजना बनाने के बजाय ऐसी नीतियाँ बनाने की कोशिश की जाती है जो संघीय ढांचे के ही खिलाफ होती है।

सबसे बड़ा संकट इस बात का है कि कुछ राजनीतिक दल आतंकवाद के खिलाफ अभियान को भी 'साम्प्रदायिकता' के चश्में से देखते हैं। वोट बैंक की राजनीति के चलते इन दलों में आतंकवाद से सहानुभूति जताने की होड़ लगने लगती है तो राष्ट्रहित और आन्तरिक सुरक्षा दोनों की खतरे में पड़ जाते हैं।

मैं सिर्फ एक उदाहरण इसी दिल्ली के बटाला हाऊस एनकाउंटर का उदाहरण देना चाहता हूं। बटाला हाऊस एनकाउंटर के मुद्दे पर देश के लगभग सभी गैर-एनडीए दल, इसमें सबसे पुराने दल से लेकर सबसे नए दल तक और सबसे भ्रष्ट कहे जाने वाले दलों से लेकर शुचिता के स्वयंभू मसीहा होने का दावा करने वाले दलों तक सभी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाकर आतंकवाद के आरोपियों के साथ सहानुभूति दिखाते और शहीद जवानों की शहादत का मजाक उड़ाते हुए नजर आये। मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि यदि कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद को वोट बैंक के तराजू में न तोला होता आज आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारे सुरक्षा बलों का पलड़ा बहुत भारी होता।

आन्तरिक सुरक्षा की भांति देश की बाहय सुरक्षा भी यू.पी.ए. सरकार की भ्रामक और दिशाहीन नीतियों के कारण बेहद कमजोर हो चुकी है। पाकिस्तान और चीन ने यू.पी.ए. सरकार की कमजोरी का फायदा उठाकर भारतीय सेनाओं के मनोबल पर गहरे आघात किए है। पिछले साल पाकिस्तान की सेना ने भारत में घुसकर हमारे

सैनिकों के सिर काटे, सैंकड़ों बार सीमा पर 'सीजफायर' का उल्लंघन किया और आतंकवादियों को भारत की सीमा में घुसने में मदद की। पाकिस्तान के साथ यूपीए सरकार की विदेश नीति 2007 में हवाना से लेकर शर्म-अल-शेख तक पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर समर्पण करने की रही।

चीन की सेनाओं ने भी भारतीय भूभाग में आये दिन घुसपैठ करने को अपना अधिकार समझ लिया है। चीन की सेनाओं द्वारा लगातार भारतीय क्षेत्र में सैंकड़ों घुसपैठें की गई। इसके बावजूद अक्टूबर महीने में डॉ. मनमोहन सिंह ने चीन जाकर एक Border Defence Cooperation Agreement (BDCA) पर हस्ताक्षर कर दिये। इस सीमा समझौते में ब्सनेम 06 यह साफ साफ कहता है कि घुसपैठ की स्थिति में दोनों सेनायें एक दूसरे को खदेड़ने का काम नहीं करेगी। यह कैसा विचित्र समझौता है? प्रधानमंत्री ने हमारी सेनाओं के हाथ बांध दिए और यह अपेक्षा की जा रही है कि भारत की बाहय सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी।

वर्ष 2014 भारत की आन्तरिक एवं बाहय सुरक्षा के लिए कई गम्भीर चुनौतियाँ लेकर आ रहा है। चूँकि इसी साल अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों समेत NATO सेनाओं की वापसी हो जायेगी इसलिए इस बात का पूरा खतरा है कि अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन जिनमें अल कायदा भी शामिल है वे अब भारत की ओर अपना रुख कर सकते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1989 में जब अफगानिस्तान से सोवियत फौजें वापिस हुई थीं तो नब्बे के दशक में भारत में आतंकवादी घटनाओं में जबरदस्त वृद्धि हुई थी और भारत की जनता को अपने सीने पर सैकड़ों घाव झेलने पड़े।

यदि हमारी सरकार आई तो राष्ट्रीय सुरक्षा के इस परिदृश्य को ध्यान में रख कर हम कड़े कदम उठायेंगे और कूटनीतिक दक्षता का प्रयोग करके अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप वातावरण बनायेंगे।

नक्सली आतंकवाद :

मित्रों, सामान्यत: आतंकवाद सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक पनपता है परन्तु नक्सली आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जो देश के केन्द्रीय इलाकों में बहुत गम्भीरता से अपने पांव पसार रही है। गत वर्ष छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं की हत्या कर दी। भाजपा इस घटना की घोर निंदा करती है और केन्द्र सरकार से और सभी राजनैतिक दलों से यह अनुरोध करती है कि वे आपसी मतभेद भुलाकर नक्सली समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय नीति बनायें। नक्सली आतंकवाद को केवल कानून व्यवस्था के नजरिये से अथवा प्रशासनिक आधार पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसके लिए प्रशासनिक कठोरता के साथ-साथ राजनैतिक इच्छाशक्ति, आर्थिक विकास और सामाजिक संवेदना सभी को ध्यान में रखकर एक व्यापक नीति बनानी होगी। इस संदर्भ में हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के कार्य प्रशंसनीय रहे हैं। हमारी केन्द्र में सरकार बनी तो हम नक्सलीय आतंकवाद से निबटने के लिए एक समेकित नीति बनायेंगे।

पड़ोसी देश एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंध :

भारत के पड़ोसी देशों के साथ अच्छे और सौहार्दपूर्ण संबंध हो, इस बात से शायद ही कोई शान्तिप्रिय व्यक्ति असहमत होगा। भाजपा भी इस बात की पक्षधर है मगर कूटनीति की बिसात पर हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। मुसीबत इस बात की है कि यू.पी.ए. सरकार ढुलमुल और लचर विदेश नीति को अपनी कूटनीति का अन्तरंग हिस्सा बना लिया है।

वर्ष 2014 भारत के लिए नई कूटनीतिक संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। इन संभावनाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए केन्द्र में एक ऐसी सरकार चाहिए जो सभी पड़ोसी देशों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों का संर्वधन करते हुए सौहार्दपूर्ण संबंध बना सके। भाजपा के पास भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने का एक कूटनीति खाका तैयार है। भाजपा सत्ता में आने पर सबसे पहले अपने पड़ोसियों से बेहतर संबंध बनाने की शुरुआत करेगी।

अफगानिस्तान :

चूंकि 2014 भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है इसलिए इस संकट की घड़ी में भारत को अफगानिस्तान का पूरा साथ देना चाहिए। पिछले साल अपनी अमरीका यात्रा के दौरान विस्तार से अफगानिस्तान के संबंध में भारत की चिंताओं को चर्चा की थी। अब अफगानिस्तान के प्रति अमेरिका का दृष्टिकोण भी परिवर्तित हो रहा है।

यही कारण है जो अमरीकी प्रशासन पहले 2014 में पूरी अमरीकी सेना को अफगानिस्तान से हटाने पर आमादा था वह अब कुछ संख्या में अपने सैनिकों को अफगानिस्तान में सिद्धांत रुप में राजी हो गया है। भारत सरकार को अफगानिस्तान के प्रमुख Stake holders और अमरीकी प्रशासन के साथ मिलकर वहां जो भी सहयोग और सहायता की आवश्यकता हो वह उपलब्ध करायी जानी चाहिए। चीन की कम्पनियां अफगानिस्तान में बड़ी तेजी से पैर पसार रही हैं। भारत सरकार को भी अफगानिस्तान में भारतीय निवेश बढ़ाने के लिए यहां के सरकारी एवं निजी उपक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए।

बांग्लादेश :

भाजपा बांग्लादेश में चुनावों के बाद से जारी हिंसा के दौर और वहां हो रहे अल्पसंख्यक हिन्दुओं के उत्पीड़न की कठोर निंदा करती है।

नेपाल :

भाजपा यह आशा करती है कि नेपाल की नव-निर्वाचित सरकार भारतीय हितों की अनदेखी नहीं करेगी और जो भी भारत विरोधी शक्तियाँ वहां से अपने मिशन को अंजाम दे रही हैं उन्हें नेपाल की सीमाओं से बाहर का रास्ता दिखायेगा।

म्यांमार :

पिछले दिनों भाजपा की मणिपुर शाखा द्वारा भारत म्यांमार सीमा पर लग रही बाड़ में काफी बड़ी मात्रा में भूभाग म्यांमार की तरफ छूटने का प्रकरण जानकारी में लाया गया था। इस बारे में मैंने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा था कि सीमा पर बाड़ लगाने का काम करने से पहले म्यांमार के साथ भारत सरकार को अपना सीमा विवाद सुलझाना चाहिए।

श्रीलंका :

श्रीलंका के साथ भारत के मधुर संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है। मगर जब से यूपीए सरकार ने सत्ता संभाली है, दोनों देशों के बीच परस्पर अविश्वास बढ़ा है। आये दिन भारतीय मछुवारों को श्रीलंका की सेना द्वारा गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि दोनों देशों के बीच मछुवारों की गतिविधि और मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर स्पष्टता नहीं है।

पाकिस्तान :

पाकिस्तान में नई सरकार के गठन के बाद उम्मीद बंधी थी कि नवाज शरीफ के नेतृत्व में शायद कोई नई शुरुआत हो मगर अफसोस पाकिस्तान अपना पुराना ढर्रा और रवैया बदल नहीं पा रहा है। शायद यू.पी.ए. सरकार की ढुलमुल 'पाकिस्तान नीति' का ही यह असर हो कि पाकिस्तान ने अपने रवैये को बदलने की जरुरत भी नहीं समझी।

एक तरफ यू.पी.ए. सरकार यह दावा करती है कि हम पाकिस्तान के साथ कोई वार्ता नहीं कर रहे तो दूसरी तरफ दोनों देशों के प्रधानमंत्री, मंत्री और अफसरों के स्तर पर लगातार बैठकें हो रही हैं। आज ही (18 जनवरी) भारत-पाक विदेश मंत्रियों की बैठक प्रारम्भ हो रही है। सरकार की तरफ से सफाई दी जा रही है कि इसे 'Dialogue' यानि 'बातचीत' की श्रेणी में न रखा जाये। अजीब बात है कि जब मंत्री मिलेंगे, अफसर मिलेंगे तो क्या मुंह पर पट्टी बांधकर बैठेंगे। किसकी आंखें में धूल झोंकी जा रही है?

जिस दिन भारत में भाजपा की सरकार गठित होगी भारत की 'पाकिस्तान नीति' में स्पष्टता और परदर्शिता आयेगी। पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया जायेगा कि यदि वह भारत से हाथ मिलाना चाहता है तो उसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। सिर्फ चेहरे बदलने से अविश्वास का माहौल नहीं बदल सकता।

चीन :

चीन इन परिस्थितियों को समझते हुए पिछले कुछ वर्षो से लगातार भारत को सामरिक मोर्चे पर कमजोर करने में लगा हुआ है। चीन की सरकार भारत सरकार पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहा है और यू.पी.ए. सरकार उसका प्रतिवाद तक नहीं कर पा रही है। भारत चीन संबंधों में सुधार और स्पष्टता तभी आयेगी जब देश में एक निर्णायक सरकार सत्ता में होगी। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो भारत और चीन के बीच अपेक्षाकृत काफी बेहतर संबंध थे।

यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। केवल एक उदाहरण। भारत और चीन के संबंधों में 1962 के युद्ध के बाद यदि केवल एक अवसर ऐसा था जब चीन ने भारत के पक्ष में अपना कोई दावा वापस लिया हो तो वह था 2003 में प्रधानमंत्री वाजपेयी की चीन यात्रा के समय जब चीन ने सिक्किम पर से अपना दावा वापस लिया। यह भाजपा सरकार की कूटनीतिक दक्षता का एक स्वर्णिम उदाहरण था।

संयुक्त राज्य अमरीका :

1998 में केन्द्र में हमारी सरकार आने बाद हमने अमरीका की इच्छा के विरूद्ध पोखरण विस्फोट किया था और इसके बावजूद 2004 में जब हमारी सरकार हटी तो अमेरिका के साथ भारत के संबंधों का वह सबसे स्वर्णिम दौर था। परन्तु यूपीए सरकार के शासनकाल में अमेरिका के साथ भारत के संबंध शिखर से सतह पर पहुंच गये प्रतीत होते हैं।

हाल ही में अमरीकी धरती पर जिस तरह भारतीय महिला राजनयिक ने उत्पीड़न की घटना सामने आई है वह इसका ज्वलंत उदाहरण है। इस घटना पर अमरीका का रवैया सरासर अनुचित और आलोचना के योग्य है।

भाजपा का अंतर्राष्ट्रीय प्रसार :

विश्वभर में फैले हुए अप्रवासी भारतीय और भारतवंशी समुदाय के मध्य भारतीय जनता पार्टी की नीति और क्षमता की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है। गत वर्ष अमेरिका यात्रा के दौरान मैने इसे अनुभव भी किया। वहां मैंने हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र भाई मोदी के प्रति अप्रवासीय समुदाय के जबरदस्त आकर्षण को भी देखा।

युवा वर्ग :

स्कूल में प्रारम्भिक शिक्षण से लेकर उसके रोजगार तक की चिंता सरकार को करनी चाहिए। पिछले एक दशक में युवाओं को निराशा हाथ लगी है कि क्योंकि उनके लिए रोजगार के अवसर सूख गये हैं। युवाओं को काम नहीं मिलेगा तो समाज में अस्थिरता बढ़ेगी।

भाजपा सत्ता में आने पर युवकों में व्याप्त निराशा को समाप्त कर हम नए उत्साह का संचार करेंगे। देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए हमें निर्माण उद्योग, पर्यटन, आयात-निर्यात, कृषि एवं खाद्य प्रस्संकरण, आई.टी. एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने में बड़ी मात्रा में निवेश करना होगा।

दसवीं कक्षा के बाद से ही युवाओं की अभिरुचि के अनुसार उन्हें 'Skill Training' देने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए ताकि दसवीं कक्षा से ही उन्हें पता चले कि राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका कहां है।

खेलकूद में युवाओं की प्रतिभा को समुचित अवसर देने के लिए हम एक खेल विकास नीति बनायेंगे ताकि 10 वर्षों के भीतर

भारत को एक 'स्पोर्टस सुपर पावर' या क्रीडा क्षेत्र की महाशक्ति के रूप में स्थापित किया जा सके।

उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए पूरे देश में सभी विश्वविद्यालयों का मान व स्तर बढ़ाया जायेगा और वहां 'शोध एवं विकास' की एक स्वस्थ परम्परा पनपे इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों में ढांचागत सुधार की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं बने इसलिए बारहवीं कक्षा के बाद 'Vocational Traning' देने वाले शिक्षण संस्थानों का पूरे देश में जाल बिछाया जाना चाहिए।

हम रोजगार केन्द्रित निवेश को प्रोत्साहित करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि देश के हर एक परिवार को कम से कम एक व्यक्ति को अर्थपूर्ण रोजगार प्राप्त हो सके।

महिला :

कांग्रेस की यू.पी.ए. सरकार ने महिलाओं को दोनों ही मोर्चे पर कमजोर रखा है।

दस वर्षों तक शासन करने के बावजूद यू.पी.ए. सरकार महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं करा पाई। यदि जनमत के दबाव में सरकार लम्बे अन्तराल के बाद लोकपाल बिल पारित कर सकती है तो महिला आरक्षण विधेयक पर भी सरकार क्या ऐसे ही दबाव का इंतजार कर रही है?

महिलाओं के प्रति अपराधों में हाल के वर्षों में जिस तरह की तेजी आई है उसमें भाजपा काफी चिंतित है। हमने यह अनुभव किया है कि सिर्फ कानून बना देने भर से बलात्कार एवं अत्याचार थमने वाले नहीं। इसके लिए सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ानी होगी ताकि समाज में नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना हो सके। इन तत्वों का पाठ्यक्रम और शिक्षा में भी समावेश आवश्यक है। तभी महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण का स्थायी समाधान संभव हो सकेगा।

अनुसूचित जाति :

आजादी के 67 वर्षों के बाद आज भी अनुसूचित जनजाति समुदाय के 75 प्रतिशत से अधिक लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं। वे न सिर्फ गरीब व अशिक्षित हैं बल्कि सामाजिक सम्मान से भी वंचित हैं। आज भी अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित अधिकांश पद इसलिए रिक्त रह जाते है क्योंकि उस वर्ग के प्रत्याशियों के पास न्यूनतम शिक्षा भी नहीं होती। यह बहुत चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस वर्ग का विकास केवल एक राजनैतिक विषय नहीं है, बल्कि इसके लिए आर्थिक सशक्तिकरण की सुविचारित योजना के साथ-साथ सामाजिक मनोविज्ञान के बदलाव का प्रयास भी आवश्यक है। भाजपा सत्ता में आने पर इन दोनों पक्षों पर पूरी जिम्मेदारी से प्रयास करेगी।

आदिवासी :

जब हमारी केन्द्र में सरकार थी तो हमने ही सबसे पहले अनुसूचित जनजाति के लिए अलग मंत्रालय बनाने का कार्य किया था। अनुसूचित जनजाति को राष्ट्र की विकास की गति के साथ मिलाने के लिए हम सरकार आने पर पुनः प्रभावी कदम उठायेंगे और आदिवासी वनवासी जनसंख्या वाले राज्यों के लिए एक साझा विकास कार्यक्रम की रुपरेखा भी बनायेंगे।

आदिवासी समुदाय की विशेष सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर एवं उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए हम एक विशेष विभाग बनाने का कार्य करेंगे। आदिवासी समुदाय के ऐतिहासिक महापुरुषों की भूमिका को भी जनमानस में अपेक्षित स्थान दिलाने के लिए हम विशेष प्रयास करेंगे, ताकि आदिवासी समुदाय अपनी पहचान और स्वाभिमान के साथ राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके।

तेलंगाना और कांग्रेस :

जिस यू.पी.ए. सरकार ने सत्ता में आते ही तेलंगाना के गठन का वादा किया था वह पांच साल की अवधि बीतने को आई है फिर भी तेलंगाना का निर्माण नहीं कर पा रही है। प्रमुख विपक्षी दल के रुप में हमने अपना खुला समर्थन इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार को दे रखा है फिर भी सरकार अपनी अन्दरूनी राजनीति के कारण इस पर अंतिम निर्णय नहीं ले पा रही है।

तेलंगाना पर कांग्रेस के पाखण्ड के कारण तेलंगाना और सीमान्ध्र दोनों क्षेत्रों में असंतोष और आक्रोश आज उस सीमा तक बढ़ गया है जिसने संपूर्ण आन्ध्र प्रदेश के लिए एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का निर्माण कर दिया है। कांग्रेस इसके समाधान की बजाय अपने राजनैतिक समीकरणों को साधने में अधिक रूचि ले रही है।

भाजपा केन्द्र में सरकार बनने के बाद तेलंगाना के निर्माण के साथ-साथ आन्ध्र प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की समस्याओं के समुचित समाधान करने के लिए एक 'Action Plan' बनायेगी।

पूर्वोत्तर राज्य :

असम में हिंसा की आग अभी ठण्डी भी नहीं हुई थी कि नगालैंड में जातीय हिंसा भड़कने की खबरें आयी हैं करीब 16 लोग नगालैंड की हिंसा में मारे गये हैं और सैकड़ों की संख्या में लोगों को अपना घर बार छोड़कर शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर होना पड़ा है। गृह मंत्रालय को चाहिए वह तत्काल स्थिति की गम्भीरता को समझते हुए वहां हिंसा रोकने के सभी प्रभावी कदम उठाये और दूसरे प्रदेशों में शरण लेने वाले नगा शरणार्थियों की सुरक्षित घर वापसी का प्रयास करे।

पूर्वोत्तर राज्यों में बेहतर सड़कें बनाने का काम अभी भी कच्छप गति से चल रहा है। लगभग सभी पूर्वोत्तर राज्यों की सड़कें बेहद खस्ताहाल हैं। उनकी अनेदखी नहीं की जानी चाहिए। विशेष रुप से कई देशों के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमायें लगी हुई हैं इसलिए इस इलाके में विश्व स्तरीय सड़कों की मौजूदगी भारत के सामरिक

हितों के लिए भी बेहद आवश्यक हैं अब जब भारत ने पानागढ़ (पश्चिम बंगाल) में 17 Moutain Corps को गठित करने का फैसला लिया है तो BRO (Border Road Organisation) को पूर्वोत्तर राज्यों के सभी सीमावर्ती इलाकों में सड़कों का निर्माण द्रुत गति से प्रारम्भ कर देना चाहिए।

दुर्भाग्यवश संसाधनों की कमी न होने के बावजूद यू.पी.ए. सरकार BRO को जितना धन आवंटित करती है उसे खर्च करने में ही काफी विलम्ब हो जाता हैं। एक तरफ चीन अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाके झमाग (Zhamag) में तिब्बत से एक all weather road से जोड़ कर अपने को भारत की सीमा तक जोड़ चुका है। वहां दूसरी तरफ यू.पी.ए. सरकार सीमा पर सड़कें बनाने के मद में आवंटित बजट को ही खर्च नहीं कर पा रही है।

भाजपा सत्ता में आने पर पूर्वोत्तर के सीमावर्ती इलाकों में विश्वस्तरीय सड़कों का निर्माण कराने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करेगी।

जम्मू कश्मीर :

जम्मू कश्मीर का विषय कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण स्वतंत्रता के बाद से आज तक समस्याओं में उलझा रहा है। अपनी कमजोर नीति और धारा 370 जैसे प्रावधानों के चलते कांग्रेस ने कश्मीर को राष्ट्र की विकास की धारा के साथ शामिल होने से वंचित रखा है।

भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानती है, वहां से भारत विरोधी शक्तियों को किसी भी प्रकार की छूट देने के विरुद्ध है और कश्मीर के गरीब आवाम तक विकास की उस रोशनी को पहुँचाने के कृतसंकल्प है, जिससे वह आजादी के 67 साल के बाद भी महरुम हैं।

कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दलों के द्वारा कश्मीर की स्थिति पर उठाये जा रहे प्रश्नों की भाजपा कठोर शब्दों में निंदा करती है। कश्मीर को विषय हमारे लिए राष्ट्र की अखंडता से जुड़ा होने के साथ-साथ भावनात्मक दृष्टि से पार्टी के साथ भी विशेष प्रकार से जुड़ा हुआ है क्योंकि कश्मीर के लिए ही हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था।

पी.एम. पद के भाजपा प्रत्याशी श्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध दुष्प्रचार :

पिछले साल देश की जनता को यूपीए शासन काल के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए भाजपा ने एक योजनाबद्ध तरीके से अपनी चुनावी रणनीति के तहत, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता जिन्हें सफलतापूर्वक शासन भी चलाने का अनुभव है, ऐसे श्री नरेन्द्र भाई मोदी को पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया। भाजपा द्वारा की गई इस घोषणा से पूरे भारतवर्ष में नई आशा और विश्वास का संचार ही नहीं हुआ बल्कि विदेशों में भी एक सकारात्मक संदेश गया।

भाजपा और उसके प्रधानमंत्री प्रत्याशी के विरुद्ध कांग्रेस राजनीतिक संघर्ष में अपने को बेहद बौना और कमजोर महसूस कर रही है। इसलिए कांग्रेस द्वारा दुष्प्रचार और कानूनी दांवपेंचों का सहारा लिया जा रहा है। कानूनी लड़ाई में भी कांग्रेस की पराजय हो रही है।

इससे खिसियाई कांग्रेस श्री नरेन्द्र मोदी पर लगातार हमले कर रही है। अपनी प्रेस कांफ्रेंस में प्रधानमंत्री ने मोदीजी को लेकर जो टिप्पणी की वह न तो किसी तथ्य पर आधारित थी और न ही वह उनके पद की मर्यादा के अनुकूल थी। गुजरात दंगों के मामले में श्री मोदी को क्लीन चिट SIT ने सुप्रीम कोर्ट को सौपी अपनी रिपोर्ट में 2011 में ही दे दी थी। कुछ दिन पहले अहमदाबाद की अदालत ने भी उनके खिलाफ हर आरोप को खारिज कर दिया। इसके बावजूद सार्वजनिक रुप से प्रधानमंत्री ने जिस रूप में उनका चित्रण किया वह गैर-जिम्मेदाराना और भर्त्सना के योग्य है।

कांग्रेस आज से नहीं कई सालों से मोदी जी को वोट बैंक राजनीति के रास्ते में बदनाम करने में लगी हुई है। गुजरात में 2002 में जो कुछ भी हुआ वह बेहद दु:खद था। परन्तु कुछ मायनों में इन दंगों को रोकने के लिए तत्कालीन गुजरात सरकार ने जो प्रयत्न किये उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं हो सकती। जैसे उस समय संसद पर हमले के प्रतिक्रिया स्वरूप भारत की सेनायें सीमा पर थीं परन्तु स्थिति बिगड़ने के चौबीस घंटे के अंदर केन्द्र सरकार से चटपट अनुमति लेकर सेना को उतार दिया गया। गुजरात सरकार द्वारा दंगा भड़कने के बाद की गई प्रभावी कार्रवाई के बावजूद आज तक कांग्रेस की गोद में खेल रहे संगठनों के द्वारा जिस-जिस प्रकार के भी आरोप लगाये गये उनकी जांच के लिए गुजरात सरकार ने पूरा सहयोग किया। हमारी सरकार ने कभी नहीं कहा कि फाइलें खो गई हैं या सबूत गायब हो गये हैं। कई प्रमुख आरोपियों को कड़ी सजायें भी हुई।

जिस ढंग से विगत 11 वर्षों से नरेन्द्र भाई की Witch hunting की गई है वह सर्वथा अनुचित है। यदि एक मामले में कोर्ट बरी करे तो सरकार कोई न कोई दूसरा प्रपंच तैयार रखती है। दूसरी तरफ 1984 के दंगों में कांग्रेस ने आज तक कितने लोगों को सजा करवाई है। उल्टे उनके नेताओं पर तो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट तक लगा दी।

अभी कुछ दिन पहले जो यह तथ्य प्रकाश में आया है कि आपरेशन ब्लू स्टार के समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ब्रिटेन की मदद ली थी इस विषय में भी सरकार को अपनी स्थिति जनता के सामने स्पष्ट करनी चाहिये।

साम्प्रदायिक दंगा एवं लक्षित हिंसा विधेयक :

यह एक विडंबना है कि लगभग सभी गैर एनडीए दल यह मानते है कि आतंकवाद जैसी विश्वव्यापी समस्या जिससे अमेरिका और पश्चिमी देश भी पूरी तरह नहीं लड़ पा रहे हैं, उससे लड़ने के

लिए कोई विशेष नियम नहीं चाहिए। उससे लड़ने के लिए तो चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, मारपीट और उठाईगिरी, जेबकतरने जैसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता की धाराएं ही पर्याप्त है। परन्तु छेड़-छाड़ से शुरू होकर मारपीट से बढते हुए हिंसात्मक रुप लेने वाले सांप्रदायिक दंगों के लिए भारतीय दंड संहिता की धाराएँ अपर्याप्त हैं और इसके लिए एक नया कानून बनना चाहिए। इस विडंबना को देश की जनता को देख रही है।

साम्प्रदायिक हिंसा के नाम पर सरकार द्वारा जो बिल लाने का प्रयास किया जा रहा है वह देश के साम्प्रदायिक ताने-बाने को ध्वस्त करने का वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित एक कुत्सित प्रयास है।

ऐसा में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब केन्द्र सरकार के गृह मंत्री ऐसा बयान दें कि अमुक समुदाय के युवकों के विरूद्ध कार्रवाई में सावधानी बरती जाए देश के इतिहास में पहली बार गृह मंत्रालय ने मुजफ्फरनगर दंगों में मारे गये लोगों की सूची साम्प्रदायिक आधार पर जारी की, तो क्या केन्द्र सरकार स्वयं साम्प्रदायिक दंगों को मजहबी रंग देकर खतरनाक राजनीति नहीं कर रही है? ऐसी सरकार से क्या निष्पक्ष साम्प्रदायिक हिंसा विरोधी कानून की अपेक्षा की जा सकती है?

उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों की राजनीति :

यूपीए की सहयोगी समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में विगत पौने दो वर्षों में सैंकड़ों साम्प्रदायिक दंगे और झड़पें हुई। स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार 30 से अधिक साम्प्रदायिक दंगे होना स्वीकार करती है। केन्द्र सरकार इस पूरे समय में हाथ पे हाथ धरे उत्तर प्रदेश सरकार को मौन समर्थन देती रही है।

इसकी चरम परिणति हाल ही के मुजफ्फरनगर दंगों में देखने को मिली। देश के प्रमुख टीवी चैनल द्वारा दिखाये गये स्टिंग आपरेशन से साफ हुआ कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार की वोट बैंक की राजनीति की मंशा नहीं होती तो मुजफ्फरनगर के दंगों को आसानी से रोका जा सकता था। परन्तु उससे भी अधिक दुखद बात यह है कि दंगों पर नियंत्रण से लेकर मुकदमें कायम करने, मुकदमें वापस लेने, राहत पहुंचाने तक सब कुछ वोट बैंक की साम्प्रदायिक नीति से ही प्रेरित दिखाई पड़ा। यदि न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता तो न जाने उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति कहां पहुंच जाती।

इतना ही नहीं 2007 में उत्तर प्रदेश की अदालतों में बम विस्फोट के आरोपियों पर से भी मुकदमें वापस लेने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार ने किया जिसे न्यायालय ने रोक दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर वोट बैंक की राजनीति भारत के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिली।

इन सबके साथ उत्तर प्रदेश की सरकार के असंवेदनशील रवैये पर भी मुझे आश्चर्य है कि मानवता और साम्प्रदायिक सौहार्द्र के उन झंडाबरदारों के मुंह में क्यों दही जमा रहा जो गुजरात के मामले पर चीत्कार मचा रहे थे। इसलिए मुजफ्फरनगर का दंगा देश के प्रशासनिक, राजनैतिक, संवैधानिक के साथ-साथ सामाजिक और बौद्धिक जगत के लिए भी एक यक्ष प्रश्न खड़ा करता है। मैं देश के बौद्धिक जगत के एक वर्ग से जो भाजपा के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त है यह अनुरोध करता हूँ कि वे राजनैतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर और किसी के भी प्रति राग और द्वेष के बिना अपनी भूमिका का सम्यक निर्वहन करना शुरू करें तो देश में बेहतर सामाजिक सोहार्द कायम हो सकेगा।

कार्यकर्ताओं से अपील :

आज भारत का लोकतंत्र जिस कुंठा, हताशा और निराशा से गुजर रहा है उससे इस लोकतंत्र को बचाने का दायित्व हमारा है। भारत में विश्व पटल पर एक समृद्ध, सामर्थ्यवान और सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित होने की सारी क्षमता विद्यमान है। उसे साकार करना हमारा दायित्व है, आज हमारे द्वार पर यह चुनौती और अवसर दोनों ही दस्तक दे रहे हैं।

अभी कुछ दिन पूर्व स्वामी विवेकानन्द सार्ध शताब्दी (150 वर्ष) के कार्यक्रम समाप्त हुए हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानन्द ने 1901 में कहा था कि मैं देख रहा हूं भारत माता प्राचीन शक्ति से युक्त होकर दिव्य आभा के साथ संपूर्ण विश्व का मार्ग दर्शन करने के लिए पुन: सिंहासनारूढ़ होने जा रही है। मैं आप सबसे यह पूछता हूं कि क्या हम सब मिलकर स्वामी विवेकानन्द के इस स्वप्न को साकार नहीं कर सकते हैं। इन सपनों को साकार करने के लिए एक कर्मयोगी जैसी लगन की आवश्यकता होगी। मैं यह मानता हूं कि यदि हम सब प्रण कर लें तो 2014 से यह स्वप्न साकार रूप लेना प्रारंभ करने वाला है।

अत: 2014 का वर्ष असाधारण वर्ष है। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन का ही नहीं भारत की भावी पीढ़ियों को प्रभावित करनेवाला और समकालीन भारत के भविष्य तय करने वाला वर्ष साबित होगा। संपूर्ण ताकत और जोश के साथ मैदान में उतरने का वक्त आ गया है। रणभेरी बज उठी है। नगाड़े निमंत्रण दे रहे हैं। अब न विश्राम का समय है न ही किसी भी असमंजस का।

मित्रों, संक्रांति का सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ चला है। पहाड़ों की बर्फ पिघलने का समय आ रहा है। मौसम बदलने वाला है। खिली धूप निखर रही है। कुछ ही महीनों में ग्रीष्म ऋतु में प्रखरता से चमकते सूर्य और तेजी से बहती हवाओं का समय आ रहा है, हम सब अपने सम्मिलित प्रयास से इसे प्रचंड आंधी में बदल सकते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि तमाम झंझावातों के बीच अंतत: भाजपा देश को एक नई रोशनी देने में सफल होगी।

'अब हवायें ही करेंगी, रोशनी का फैसला
जिस दिए में जान होगी, वह जला रह जायेगा।'

■

राजनीतिक प्रस्ताव

कांग्रेस से मुक्ति चाहता है देश

राष्ट्रीय परिषद् बैठक के दूसरे दिन 19 जनवरी 2014 को लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका समर्थन भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू एवं राज्यसभा में भाजपा के उपनेता श्री रविशंकर प्रसाद ने किया। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्ववाली एनडीए सरकार की महान विकास गाथा को श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए ने पूरी तरह बर्बाद किया। प्रस्ताव में जनता से आह्वान किया गया है कि वह एक बेहतर भारत के लिए भाजपा को निर्णायक जनादेश दे।

हम यहां इस प्रस्ताव का पूरा पाठ प्रकाशित कर रहे हैं :

हाल में हुए विधान सभा चुनावों में भाजपा का शानदार प्रदर्शन

भारतीय जनता पार्टी ने हाल में हुए विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की है। लोक सभा चुनाव से मात्र कुछ महीने पहले यह जीत भरोसे का दृढ़ प्रमाण है। भाजपा विभिन्न राज्यों में पार्टी में अपना विश्वास जताने के लिए लोगों को धन्यवाद और कृतज्ञता देती है। राष्ट्रीय परिषद अपने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन करती है जो तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं और जिन्होंने खुद दो बार अपने नेतृत्व में पार्टी को मध्य प्रदेश में शानदार जीत दिलायी है और इस बात तो उन्होंने दोतिहाई बहुमत भी हासिल किया है। इसी तरह श्री रमण सिंह भी बधाई के पात्र हैं जो सफलतापूर्वक छत्तीसगढ़ में तीसरे कार्यकाल के लिए जनता का भरोसा पाने में कामयाब हुए हैं। इन दोनों राज्य सरकारों के प्रदर्शन और जनहित कार्यक्रमों की व्यापक सराहना हुई है। श्रीमती वशुंधरा राजे भी प्रशंसा पाने की हकदार हैं जिनके नेतृत्व में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान में लगभग तीन-चौथाई बहुमत हासिल किया है। दिल्ली में डा. हर्षवर्धन और पार्टी को शुभकामनाएं, यहां भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हालांकि कुछ सीटों के अंतर से पार्टी बहुमत से दूर रह गयी।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की विदाई की घोषणा और राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार घोषित करने से कांग्रेस पार्टी का बचना

कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कुशासन, कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और दंडनीय उदासीनता ने भारत को ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां लोग सिर्फ पीड़ा झेलते हैं और असुरक्षित महसूस करते हैं। 2014 में, भारतीयों को आशा और उत्साह के साथ बदलाव की प्रतीक्षा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब यह घोषणा की कि वह चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए उपलब्ध नहीं होंगे तो यह घटना ऐसी दिखी मानो देश की जनता कब से इस पल की प्रतीक्षा में थी। उनके पास कामयाबी के तौर पर दिखाने के लिए कुछ नहीं है इसलिए उन्होंने इतिहास से उनके साथ न्याय करने की उम्मीद जतायी। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोई ऐसी छाप नहीं छोड़ी है जिससे इतिहास उन्हें कोई अहम स्थान दे सके।

डा. मनमोहन सिंह कभी जन नेता नहीं रहे, अक्सर उन्हें अच्छा अर्थशास्त्री कहा गया लेकिन उनके दस साल के शासन ने भारत की विकास गाथा को ध्वस्त कर दिया। सुशासन, नीतिगत पहल, निर्णय, सुचिता और निष्पक्षता का गंभीर अभाव हो गया। कांग्रेस नेताओं और कई वरिष्ठ मंत्री लगातार ही एक अभियान चला रहे थे कि राहुल गांधी को कांग्रेस का पीएम उम्मीदवार घोषित किया जाये। डा. मनमोहन सिंह ने भी अपनी दुर्लभ प्रैसवार्ता में यही संकेत दिया था। राहुल गांधी ने खुद एक मीडिया साक्षात्कार संकेत दिया कि वह कोई भी जिम्मेदारी स्वीकारने को तैयार हैं। अब, अचानक से हमने यह घोषणा सुनी है कि कांग्रेस पार्टी की यह परंपरा नहीं है कि वह प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे। यह महज एक बहाना है। वास्तव में यह हकीकत को पहचानना था। नेतृत्व की गुणवत्ता, सुशासन व सत्यनिष्ठा के रिकार्ड और इन सबसे बढ़कर लोकप्रियता के मामले में श्री नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी का कोई मुकाबला नहीं है। कई सर्वेक्षणों में राहुल गांधी लोकप्रियता के मामले में श्री

मोदी से काफी पीछे है। कांग्रेस यह जानती थी कि वह राहुल गांधी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर राजनीतिक तौर पर भाजपा और श्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकती। चुनाव जब भी हों, हार निश्चित है, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित न करके बच निकलना ही बेहतर समझा। हकीकत तो यह है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने देश को जितनी पीड़ा और समस्या ग्रस्त किया है उसके लिए राहुल गांधी भी उतने ही जिम्मेदार हैं क्योंकि सरकार ने उनके नियंत्रण में भी काम किया है। कांग्रेस को जाना चाहिए, देश यह देखने को उत्सुक है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार 1998 में जब सत्ता में आयी तो उस समय भारत की विकास दर मात्र 4.8 प्रतिशत थी। अच्छे नेतृत्व, दृढ़ नीतिगत पहल, सुशासन और प्रेरक प्रदर्शन के साथ एनडीए ने जब मई 2004 में सत्ता छोड़ी तो उस समय विकास दर असाधारण 8.5 प्रतिशत के स्तर पर थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की महान विकास गाथा को श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए ने पूरी तरह बरबाद किया

श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार 1998 में जब सत्ता में आयी तो उस समय भारत की विकास दर मात्र 4.8 प्रतिशत थी। अच्छे नेतृत्व, दृढ़ नीतिगत पहल, सुशासन और प्रेरक प्रदर्शन के साथ एनडीए ने जब मई 2004 में सत्ता छोड़ी तो उस समय विकास दर असाधारण 8.5 प्रतिशत के स्तर पर थी। एनडीए ने भारतीय अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत ढांचा दिया जिसमें मुद्रास्फीति नियंत्रित थी, समानता के साथ विकास था और रोजगार के अच्छे अवसर थे।

वाकई यह अनुकरणीय था क्योंकि यह सब बेहद कठिन परिस्थितियों और प्रतिकूल वैश्विक माहौल के साये में हासिल किया। उस समय पोखरण-।। परमाणु परीक्षण के चलते अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगे, करगिल युद्ध हुआ, पूर्वी-एशियाई संकट, गुजरात में भयंकर भूकंप, 2001 में सूखा और 2002 में उड़ीसा में चक्रवात आया था। हकीकत तो यह है कि यूपीए सरकार ने वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आर्थिक समीक्षा 2004-05 के पेज संख्या 1 पर खुद इस तथ्य को स्वीकार करते हुए लिखा, ''कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सुधार तथा उद्योग और सेवा क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन की बदौलत अर्थव्यवस्था ने 2003-04 में 8.5 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की है जो कि 1975-76 और 1988-89 को छोड़ अब तक की सर्वोच्च है।'' वाकई यह एक त्रासदी है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने इसे पूरी तरह चौपट कर दिया और इसे घटाकर 5 प्रतिशत से कम यानी लगभग 4.8 प्रतिशत पर लाकर रख दिया। आने वाले कुछ महीनों में इसमें सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। डा. मनमोहन सिंह की सरकार, जो कि प्रभावी तौर पर श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व और नियंत्रण में है, ने भारत की विकास गाथा को नष्ट कर दिया है।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के घोटालों ने देश की छवि धूमिल की

भाजपा पिछले कुछ वर्षों से यह स्पष्ट मानती रही है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार आजादी के बाद से अब तक की सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार है। हर दिन यह छवि और मजबूत हुई है। वाकई यह भ्रष्ट गठबंधन है। उच्च स्तर पर साठ-गांठ है और इस सरकार के राजनीतिक नेतृत्व के संरक्षण में अश्वपरेटर तथा बिचौलिये मिली-भगत से एक के बाद एक घोटाले कर कई लाख करोड़ रुपये भ्रष्ट तरीके से कमा चुके हैं। इन घोटालों में सरकार के राजनीतिक नेतृत्व के महत्वपूर्ण तत्वों की मिलीभगत रही और कई मामलों में वे सक्रिय तौर पर सहभाग रहा है। एक के बाद एक घोटाले ने देश को हिलाकर रख दिया है। आज इनकी गिनती रखना भी मुश्किल हो गया है। टूजी लाइसेंस के आवंटन में 1.76 लाख करोड़ रुपये के महाघोटाले से लेकर कोयला ब्लॉक आवंटन में व्यापक धांधली (1.86 लाख करोड़ रुपये का घोटाला) और 70 हजार करोड़ रुपये का राष्ट्रमंडल खेल घोटाला जहां संसद में आश्वासन के बाद भी शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी। यूपीए सरकार के घोटालों की फेहरिस्त काफी लंबी है। कोयला घोटाले में सरकार ने खुद अदालत के समक्ष धांधली स्वीकार की है लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री उनकी भूमिका की जांच करने की इजाजत सीबीआई को नहीं दे रहे हैं, जबकि जिस समय यह धांधली हुई, उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार उनके ही पास था। विभिन्न अदालतों ने यूपीए सरकार की कार्यप्रणाली, अनियमित्तता और भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों को लेकर जो सख्त टिप्पणियां की हैं, उससे गंभीर कुशासन का संकेत मिलता है।

सरकार ने विदेशी बैंकों में पड़े कालेधन (कई लाख करोड़ रुपये) को वापस लाने के लिए कोई पहल नहीं की है। भाजपा इस संबंध में आवश्यक और कड़े कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार को अगस्ता-वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे को रद्द करने को मजबूर होना पड़ा क्योंकि इस सौदे में बड़ी घूस दी गयी थी। सरकार ने शुरु में इस सौदे के बचाव की कोशिश की और आयकर विभाग को इसकी जांच करने से रोका भी गया। अब इटली में जांच के दौरान नये तथ्य सामने आ रहे हैं जिसके चलते भारत में आगे और गंभीर जांच की जरूरत है। इटली की जांच में खुलासा हुआ है कि घूस लेने वाले कुछ लोगों के कोड नाम ''एपी'' और ''फैमिली'' हैं। आखिर ये लोग कौन हैं और क्या इनका संबंध भारत में मौजूदा

सत्ताधारी वर्गों से है, ये सवाल चिंताजनक हैं, जिनकी जांच की जरूरत है।

भाजपा का आक्रामक अभियान, मीडिया के खुलासे, अदालतों के हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार के खिलाफ के खिलाफ बना माहौल, अगर ये सब बातें नहीं होती तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार किसी जांच की अनुमति नहीं देती क्योंकि घोटालों के निशान उसके नेताओं की दहलीज तक जा रहे हैं। टूजी घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति की गरिमा के साथ जिस तरह इसके अध्यक्ष ने समझौता किया, उससे यही साबित होता है कि वह एक कांग्रेसी की तरह व्यवहार कर रहे थे और उन्होंने भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सबूतों की अवलेहना कर एक शर्मनाक रिपोर्ट दी तथा अन्य सदस्यों के असहमति पत्रों में भी कांट-छांट की जिससे कांग्रेस की असलियत पता चलती है। आदर्श घोटाले में भी जिस शर्मनाक ढंग से कांग्रेस सरकार ने महाराष्ट्र के अपने पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही मौजूदा गृह मंत्री का बचाव किया, उससे एक बार फिर यह तथ्य साबित हो गया कि कांग्रेस के नेता खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उनकी सरकार बेशर्मी से उन्हें बचाती है। हाल में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके परिजनों के नाम पर एक व्यवसायी से लोन सौदे का मामला भी भ्रष्टाचार तथा काम के बदले घूस लेने का सीधा मामला बनता है। भाजपा संसद के दोनों सदनों से लोकपाल विधेयक पारित होने पर संतोष प्रकट करती है क्योंकि पार्टी ने इसके लिए सराहनीय पहल की और लगातार कोशिशें की। कांग्रेस सरकार ने कोई न कोई बहाना बनाकर इसमें विलंब करने की कोशिश की लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के व्यापक भ्रष्टाचार केखिलाफ देश में उभरी सामूहिक चिंता के परिणामस्वरूप लोकपाल की संस्था ने वास्तविक रूप लिया।

आंतरिक सुरक्षा को गंभीर खतरा

भारत की आंतरिक सुरक्षा को गंभीर खतरा है। आतंकवादी समूह योजनाबद्ध ढंग से षड्यंत्र कर हमले करते हैं। हाल के वर्षो में लश्कर-ए-तैबा के अलावा इंडियन मुजाहिदीन देश का सबसे खतरनाक संगठन बनकर उभरा है जिसका मकसद बदला लेना और भीड़ भरे इलाकों में हमले करना है। इसका नियंत्रण करने वाले अब भी पाकिस्तान में सुरक्षित पनाह ले रहे हैं। यह बात जगजाहिर है कि लश्कर-ए-तैबा को पाकिस्तान में सत्ताधारी प्रतिष्ठान और सेना से पूरा संरक्षण मिल रहा है।आतंकवादी संगठन अब राजनीतिक रैलियों पर भी हमले कर रहे हैं। पटना में श्री नरेंद्र मोदी की विशाल ''हुंकार रैली'' (भारत के इतिहास में सबसे बड़ी रैलियों में से एक) पर आतंकी हमला इस बात का प्रमाण है कि आतंकी अपनी इच्छा से हमले कर सकते हैं। रैली की योजना कई महीने पहले बनायी गयी थी और प्रशासन को उचित तरीके से सूचित भी किया गया। लेकिन विशुद्ध रूप से वोट बैंक की राजनीति की खातिर राज्य सरकार ने जानबूझकर आवश्यक सुरक्षा प्रक्रिया का पालन नहीं किया और भारत सरकार ने भी पर्याप्त उपाय सुनिश्चित नहीं किये। यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि पटना पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उपायों के साथ तैयार थी लेकिन आखिरी क्षण पर इसे लागू क्यों नहीं किया गया, यह अब तक रहस्य बना हुआ है और जिम्मेदारी तय करने के लिए इसकी तटस्थ तथा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। असल मकसद तो श्री नरेंद्र मोदी को भारी भीड़ को संबोधित करने से रोकना था। आतंकवादियों ने वहां भगदड़ फैलाने के इरादे से ही श्रृंखलाबद्ध विस्फोट किये थे। यह बड़े गर्व की बात है कि श्री मोदी ने सुरक्षा बलों के सुझाव को दरकिनार कर महान साहस का परिचय देते हुए रैली को संबोधित किया और अति तनावपूर्ण स्थिति में भी लोगों को शांति कायम रखने की अपील की। हम बिहार के लोगों को भी सैल्यूट करते हैं जिन्होंने बार-बार बम धमाकों और जख्मी होने के बावजूद अदम्य साहस दिखाया तथा अफरा-तफरी नहीं फैलायी और श्री नरेंद्र मोदी को ध्यानपूर्वक सुना। इंडियन मुजाहिदीन के जिस समूह ने बोधगया मंदिर परिसर पर हमला किया था, उसी ने पटना रैली में श्रृंखलाबद्ध धमाके किये। उन्हें पता था कि सरकार वोट बैंक के दबाव में उन पर निशाना नहीं साधेगी। कई लोगों की जान गयी और रैली मैं मौजूद नेता ईश्वर की कृपा से बचे। देश के कुछ भागों के साथ बिहार भी अब धीरे-धीरे आतंकवादियों के लिए सुरक्षित शरणस्थली बन रहा है। कुख्यात आतंकी यासीन भटकल ने बिहार में कई आतंकियों की भर्ती की और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया था जिन्होंने बाद में योजनानुसार आतंकवादी हमले किये, इसके बावजूद समय रहते इन आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर वोट बैंक की राजनीति का हावी होना

भारत में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को अब वोट बैंक की राजनीति की खातिर गिरवी रख दिया गया है। यूपी सरकार ने सार्वजनिक तौर पर आतंकवादियों के खिलाफ लंबित मामलों को वापस लेने की कोशिश की जबकि ऐसे मामले सिर्फ अदालत के हस्तक्षेप से ही रोके जा सकते हैं। भारत के गृह मंत्री ने बड़ी बेशर्मी के साथ मुख्यमंत्रियों से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ मामलों की समीक्षा करने को कहा है। यह पूरी तरह असंवैधानिक है। दोषी या निर्दोष होने का फैसला आस्था या धर्म के आधार पर नहीं किया जा सकता। यह अपराध के प्रकार और गंभीरता पर निर्भर करता है। ऐसा निर्देश पुलिस और सुरक्षा बलों को सिर्फ हतोत्साहित करेगा। यह पूरी तरह तुष्टीकरण है। श्रीमान शिन्दे ने इससे पहले केसरिया और हिन्दू आतंक जैसी शब्दावली का प्रयोग किया है। शायद वह यह भूल गये हैं कि आतंकवाद का कोई रंग या धर्म नहीं होता। वह यह भी भूल गये कि केसरिया और हिन्दू परंपरा हमारी सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत के उत्तम स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। स्वाभाविक रूप से उनके इन बयानों से पाकिस्तान में

आतंकवादियों को दिल से प्रसन्नता हुई। मुंबई में 26/11 के हमले के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद ने सार्वजनिक तौर पर इसका स्वागत किया। श्री शिन्दे ने अफसोस प्रकट करते हुए कहा था कि उनका इरादा भाजपा या आरएसएस को आहत करने का नहीं था, लेकिन इससे पाकिस्तान और वहां मौजूद आतंकवादी निराधार आरोप लगाने और उंगली उठाने से नहीं रुकेंगे।

भाजपा का दृढ़ विश्वास है कि पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य तब तक नहीं हो सकते जब तक कि वह उसकी जमीन से गतिविधियां चलाने वाले आतंकी तत्वों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई नहीं करता- इस प्रतिबद्धता को पाकिस्तान ने जनवरी 2004 में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति मुशर्रफ के बीच हुए समझौते में स्वीकार किया।आतंकवाद से लड़ाई के लिए क्षमता विस्तार की जरूरत है। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति हमेशा ही आतंकवादियों और उनके संरक्षकों की हिम्मत बंधायेगी। केंद्र और राज्य दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी आतंकवाद से लड़ने की है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और संघवाद का सम्मान, दोनों साथ चलने चाहिए।

राष्ट्रीय परिषद हाल में मुजफ्फरनगर और यूपी के अन्य भागों तथा असम में हुई सांप्रदायिक हिंसा की जोरदार तरीके से भर्त्सना करती है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों की लगातार ही भेदभाव और तुष्टीकरण की नीति रही है जिससे सिर्फ सांप्रदायिक तनाव और मतभेद पनपा है।

माओवाद और नक्सलवाद का खतरा भी कायम है। वे देश के विभिन्न भागों में निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं और अच्छी खासी संख्या में सुरक्षा बलों की जान ले रहे हैं। यह एक राष्ट्रीय समस्या है लेकिन सरकार के पास इससे निपटने के लिए विजन और दिशा का अभाव है।

भाजपा पुन: यह दुहराती है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता से छेड़छाड़ करने की किसी भी साजिश का सख्ती से विरोध किया जायेगा। कश्मीरी पंडित जिन्हें उनकी मातृभूमि छोड़ने को मजबूर किया गया उन्हें गरिमामय तरीके से अपने घरों को लौटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा और अवसर मुहैया कराया जाये।

''सत्यमेव जयते''

गुजरात सरकार पिछले 12 साल से झूठ पर आधारित निरंतर और दुर्भावना से प्रेरित अभियान का सामना कर रही है। यह अभियान कांग्रेस और कुछ कांग्रेस प्रोत्साहित गैर-सरकारी संगठनों और बुद्धिजीवियों के द्वारा चलाया गया है, जिनके मन में भाजपा के खिलाफ नफरत है। सांप्रदायिक तनाव फैलाने और उसका राजनीतिक इस्तेमाल करने के मामले में कांग्रेस का पूरा इतिहास जगजाहिर है। गुजरात में भी कांग्रेस जब सत्ता में थी तो वहां कई दंगे हुए। दंगे दुर्भाग्यपूर्ण हैं और इनके लिए जो भी जिम्मेदार हो उसे सजा मिलनी चाहिए। गुजरात में 2002 में हुए दुर्भाग्यपूर्ण दंगों में सुनवाई के बाद कई लोग दोषी करार दिये जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी निगरानी में कुछ गंभीर मामलों की जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल गठित किया था। उनके अनुसंधान के बाद कोर्ट में ट्रायल हो रहा है। गोधरा मामले में भी अदालत ने एसआईटी की जांच के आधार पर कई लोगों को साबरमती एक्सप्रैस के डिब्बे में आग लगाने का अपराधी साबित होने पर दोषी करार दिया है। गोधरा घटना की साख पर भी सवाल उठाते हुये पूर्व में एक अभियान चलाया गया था।

दुर्भाव से प्रेरित इस अभियान का एकमात्र मकसद झूठ और मनगढंत तथ्यों के आधार पर किसी भी तरह श्री नरेंद्र मोदी को फंसाना था। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी ने भी उनके खिलाफ प्रायोजित शिकायतों की जांच की और उसे बेबुनियाद पाया। इस जांच रिपोर्ट को शिकायतकर्ता का पक्ष सुनने के बाद अहमदाबाद की एक अदालत ने स्वीकार भी कर लिया। सत्य शाश्वत है और झूठ बेनकाब हो जाता है। श्री नरेंद्र मोदी ने झूठ पर आधारित प्रायोजित दुष्प्रचार का बिना विचलित हुये सामना किया और आज न्याय की कसौटी पर सच्चाई सबके सामने है। क्या इस झूठ को फैलाने वाले या इस दुष्प्रचार के चलते झूठ पर विश्वास करने वाले लोग अब आत्मनिरीक्षण करेंगे। इसमें कोई अचरज की बात नहीं कि जिन लोगों ने गुजरात में प्रायोजित अभियान चलाया था वे मुजफ्फरनगर दंगों ओर वहां पीड़ितों के साथ अमानवीय ज्यादती पर मौन हैं।इस प्रायोजित अभियान के बीच विश्वास की बात यह है कि श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ऊर्जा गुजरात में चहुंमुखी विकास और बेहतरीन सुशासन देने में लगायी। पिछले 12 वर्षों से राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ है। वहां शांति, सौहार्द, भाईचारा के साथ समाज के सभी वर्गों का चहुंमुखी विकास हुआ है जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं जिनकी विकास दर बाकी देश की तुलना में गुजरात में सर्वाधिक है। श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात की जनता ने बारंबार चुना है और देश की जनता उन्हें राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए आशीर्वाद देने की प्रतीक्षा कर रही है। हालांकि डा. मनमोहन सिंह ने जब एक निंदनीय बयान दिया कि श्री मोदी अगर भारत के प्रधानमंत्री बने तो यह देश के लिए विनाशकारी होगा, तो वह भी झूठ के उस अभियान में शामिल हो गये जो हमेशा असफल हुआ है और आगे भी असफल होगा।

महिला सुरक्षा

भारत को अगर आगे बढ़ना है तो देश की महिलाओं को आदर और सुरक्षा का अहसास होना जरूरी है। कुछ विधायी और प्रशासनिक उपाय किये गये हैं जिनका भाजपा ने पूरी तरह समर्थन किया है लेकिन देश के विभिन्न भागों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का दौर जारी है जो गंभीर चिंता का विषय है। यह सामूहिक उत्तरदायित्व का मामला है जहां सिर्फ प्रतीकात्मक कार्रवाई को छोड़कर पुलिस सुधार

और कानूनी ढांचे को प्राथमिकता के आधार पर सुधारना होगा, साथ ही उचित निगरानी की जरूरत भी है ताकि दोषी के लिए सजा सुनिश्चित की जा सके। भाजपा का दृढ़ विश्वास है कि महिलाओं को उचित सम्मान, पहचान, आदर और सुरक्षा दिये बगैर भारत तरक्की नहीं कर सकता।

निष्प्रभावी और अक्षम विदेश नीति

भारत की विदेश नीति का प्रबंधन दयनीय स्थिति में है। भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े के साथ अमेरिका में जैसा बर्ताव हुआ है उससे यह छाप और मजबूत दिखाई देती है। विदेश नीति का संचालन भारत जैसे विशाल और शक्तिशाली देश के सामरिक हितों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। निर्णय तदर्थ आधार पर हो रहे हैं जो प्रभावी नहीं हो पाते। आज सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंध ठीक नहीं हैं। चीन बार-बार हमारे भूभाग में घुसपैठ कर रहा है। पाकिस्तानी सेना और उनके द्वारा संरक्षित आतंकवादी समूह नियंत्रण रेखा के निकट लगातार जो हमले कर रहे हैं उन्हें भी प्रभावी तरीके से नहीं संभाला गया है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि भारतीय सुरक्षा बलों के मनोबल और स्वाभिमान के साथ समझौता न किया जाये। भाजपा पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हमलों की जोरदार भर्त्सना करती है। सरकार को इन दो देशों में हिन्दू अल्पसंख्यकों की हिफाजत और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करने चाहिए। भाजपा की मांग है कि तमिलनाडु और आसपास के इलाकों के मछुआरों को श्रीलंकाई सुरक्षा बलों द्वारा उत्पीड़न के खिलाफ उचित सुरक्षा और संरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। सीमा सुरक्षा के अलावा हमारी सामुद्रिक सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जिसके लिए उचित कदम उठाने की जरूरत है। हम विश्व के एक अहम देश के रूप में भारत की गरिमा और आत्म-सम्मान को सुदृढ करने को प्रतिबद्ध हैं।

संस्थाओं का पतन

विवादों से घिरी यूपीए सरकार ने योजनाबद्ध रूप से संस्थाओं की गरिमा पर हमला किया है। आज श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) की बढ़ती भूमिका के चलते योजना आयोग लगभग अप्रासंगिक हो गया है। सीएजी ने जब सरकार से उसकी कारगुजारियों की जवाबदेही तय कराने की कोशिश की तो वरिष्ठ मंत्रियों ने इस संवैधानिक संस्था पर हमला बोल दिया। इसी तरह संदेहास्पद नियुक्ति कर सीवीसी जैसी संस्था की गरिमा से भी समझौता किया गया, आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने इस नियुक्ति को निरस्त कर दिया। सरकार किस कदर सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, यह बात जगजाहिर है। कई मंत्रियों के भ्रष्टाचार और घोटालों पर जब सवाल उठाये गये हैं या निर्णय प्रतिकूल रहा है तो उन्होंने न्यायपालिका पर भी सवाल उठाने की कोशिश की है। कई बार तो कुछ मंत्रियों ने चुनाव आयोग को भी नहीं बक्शा है।

पूर्वोत्तर की स्थिति

भाजपा का साफ मानना है कि बांग्लादेशी घुसपैठ में कांग्रेस की साठ-गांठ असम की हिंसा की जड़ है। इस बात पर आम सहमति की जरूरत है कि असम की समस्या भारतीय बनाम् विदेशी मुद्दा है न कि हिन्दू बनाम मुस्लिम मुद्दा। हालांकि जो हिन्दू धार्मिक कारणों से पाकिस्तान और बांग्लादेश छोड़ने को मजबूर किये गये हैं उन्हें उचित सुरक्षा और संरक्षा और शरणार्थी का दर्जा दिया जाना चाहिए। एक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) हो जिसमें असम में मतदाता सूची से गैर-नागरिकों के नाम मिटाये जायें। आदिवासी बहुल इलाकों की पवित्रता भी अक्षुण रखनी चाहिए। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली सरकार असम समझौते को पूरी तरह भूल गयी है जो कि श्री राजीव गांधी ने किया था। भाजपा बांग्लादेश के साथ जल्दबाजी में किये किसी भी सीमा विवाद के समाधान के खिलाफ है। सबसे महत्वपूर्ण घुसपैठ के मुद्दे सहित सभी मुद्दों पर बांग्लादेश के साथ व्यापक पहल की जरूरत है। नागा मुद्दे का स्थाई समाधान निकालने के लिए भी तेजी से प्रयास होने चाहिए। कुछ चिंताजनक खबरें आ रही हैं कि मणिपुर में सीमा पर बाढ बनाते समय विश्व प्रसिद्ध जैव-विविधता पार्क के कुछ हिस्से और अन्य क्षेत्रों को म्यांमार को दे दिया गया है जो बेहद चिंताजनक मामला है। सरकार इसे ठीक करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। यह निंदनीय है कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों को भारतीय पासपोर्ट पर चीन नत्थी वीजा दे रहा है। अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा।

इंडिया फर्स्ट - भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के कार्यकाल के भारत को पुनः साकार करना और देश को आगे बढ़ाना

आज जैसे-जैसे लोक सभा चुनाव के निकट आ रहे हैं, देश में बदलाव की सशक्त भावना दिखाई दे रही है। लोग भारत को कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दस साल के कुशासन, भ्रष्टाचार, महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और घटती विकास दर से मुक्त चाहते हैं। वे भारत को विकसित होते देखना चाहते हैं। वे बडे गर्व के साथ श्री अटलबिहारी वाजपेयी की सरकार के प्रदर्शन और सुशासन को याद करते हैं जिससे भारत उच्च विकास दर के साथ आगे बढ़ा। वही आज निराशा और हताशा है। यह बडे गर्व की बात है कि जब यूपीए के अधीन देश की विकास दर पांच प्रतिशत से भी नीचे है तो उसी समय एनडीए शासित राज्य जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, गोवा और पंजाब 10 प्रतिशत से अधिक शानदार विकास दर दर्ज कर रहे हैं। यह सब सुशासन और समानता के साथ विकास की नीतियों से संभव हुआ है।

भारत बदलाव चाहता है - भारत बदलाव और कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने का हकदार है

शेष पृष्ठ 28 पर

यूपीए ने देश की अर्थव्यवस्था को कई दशक पीछे धकेल दिया

राष्ट्रीय परिषद् बैठक के पहले दिन 18 जनवरी 2014 को राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने आर्थिक प्रस्ताव प्रस्तुत रखा, जिसका अनुमोदन भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने किया। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि संप्रग को राजग से ठोस आर्थिक विकास विरासत में मिला था। उस समय आर्थिक मजबूती थी। लेकिन संप्रग ने इस विरासत को गंवा दिया और देश की अर्थव्यवस्था को कई दशक पीछे धकेल दिया।

हम यहां इस प्रस्ताव का पूरा पाठ प्रकाशित कर रहे हैं :

व्यर्थ गया दशक

यूपीए के शासनकाल में देश को एक अन्धकारमय दशक का सामना करना पड़ा है। कांग्रेसनीत यूपीए सरकार सभी आर्थिक मानदण्ड़ों पर असफल रही है और परिणामस्वरूप आज देश निराशा महसूस कर रहा है। इस दशक के दौरान मंहगाई, भ्रष्टाचार, ब्याज दरें, राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा, बेरोजगारी, कृषि लागत मूल्य कई गुणा बढ़ गयी जिससे लोगों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है। वही दूसरी ओर, सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार के अवसर, बुनियादी ढ़ांचे का विकास मजदूरों की वास्तविक मजदूरी किसानों का लाभांश कम हो गया। यह आश्चर्यजनक है कि जहां वैश्विक स्तर पर विकास दर बढ़त दर्ज कर रही है, वही भारत में विकास दर नीचे की ओर गिर रहा है। कांग्रेस का 10 वर्षो का शासनकाल देश के लिए घातक सिद्ध हुआ है।

यूपीए शासन काल में आर्थिक, वैश्विक मंदी के कारण कम नेतृत्व के पूर्ण अभाव, दोहरे शक्ति केन्द्र, विचारों का दिवालियापन, विज़न की कमी, विनाशकारी नीतियां और ज्यादा अन्तर्निहित भ्रष्टाचार के कारणों से अधिक हुई। यह एक व्यर्थ गया दशक था जिसमें देश में सभी क्षेत्रों में गिरावट आई, चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ-व्यवस्था, नीतियां या प्रशासन का क्षेत्र हो। कुल मिलाकर यह तेजी से गिरते नैतिक पतन का दशक सिद्ध हुआ।

मंहगाई, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी असफलता बन गई है। उन्होंने यह बात कई अवसरों पर स्वीकार भी की। महंगाई के साथ-साथ भ्रष्टाचार भी यूपीए शासन काल का एक दूसरी बड़ी पहचान बन गयी है। इन दोनों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया है। इस काल में सभी क्षेत्रों में गिरावट हुई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक लगातार नकारात्मक जोन में रहा। मैन्युफैक्चरिंग, खनन, इस्पात, विद्युत और बुनियादी ढ़ांचे सहित सभी क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। यू.पी.ए. का किसान विरोधी और श्रमिक विरोधी नीतियों के कारण किसान और श्रमिक बुरी तरह प्रभावित हुये हैं। जैसे आय और क्षेत्रीय असंतुलनों में वृद्धि हुई है उसी प्रकार बेरोजगारी भी बढ़ी है। कुल मिलाकर देश को नुकसान हुआ है और इसकी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी की बनती है।

ठोस विरासत

सप्रंग को मई 2004 में 8.4 प्रतिशत ठोस आर्थिक विकास विरासत में मिला। उस समय आर्थिक मजबूती थी। हम कम महंगाई दर एवं तेज इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधि के साथ-साथ सरप्लस सचल खाता वाले देश थे जिसके कारणवश रोजगार में तेज वृद्धि सुनिश्चित होती थी। देश में ब्याज की दरें कम थीं जिनके कारण निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई। एक नई सरकार के लिए आय बढ़ाने के लिए यह एक बेहतर स्थिति थी। वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम को 8 जुलाई 2004 को अपने पहले बजट भाषण में यह स्वीकार करना पड़ा कि : "आर्थिक मूलभूत मानक सुदृढ़ प्रतीत होते हैं और भुगतान संतुलन भी मजबूत है।" और "विकास दर को उत्पादन में बढ़त, कृषि में मूल्य संर्वधन, उद्योगिक उत्पादन में निश्चित सुधार और सेवा क्षेत्र के नियमित उत्साह वाले प्रदर्शन को बनाया रखा जायेगा।''

इसके बजाय सप्रंग सरकार ने इन सभी अवसरों को गंवा दिया और देश की अर्थव्यवस्था को कई दशक पीछे धकेल दिया। संप्रग को राजग से 8.4 की विकास दर और 4 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर

विरासत में मिली थी परन्तु उसने फलते-फूलते आर्थिक वातावरण को निराशा में बदल दिया और अब जबकि वह सत्ता से बाहर होने जा रही है तो ठीक उलट विकास दर 4.8 प्रतिशत के आसपास है और मुद्रास्फीति दोहरे अंक में है।

महंगाई - संप्रग शासनकाल में महंगाई अधिकतम काल के लिए दोहरे अंक में ही रही। सरकार ने कई बेतुके तर्क देकर मूल्यों में इस वृद्धि का बचाव किया। पहले उसने कहा कि पूरे विश्व में मूल्य बढ़ रहे हैं परन्तु तथ्य यह है कि इस काल में समूचे विश्व में मूल्यों में 3 प्रतिशत -5 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। फिर तर्क यह दिया गया लोग ज्यादा खा रहे इससे ये कि मांग बढ़ गई है। सारे देश में हुई आलोचना के बाद वे अपनी इस बात से शीघ्र पीछे हट गये। तत्पश्चात उन्होंने इसे विश्व में ईंधन के मूल्यों में वृद्धि को कारण बताया। जबकि तथ्य यह है कि ईंधन का वैश्विक मूल्य कई वर्षों तक लगभग 100 अमरीकी डालर प्रति बैरल के आस-पास है तब भी सरकार ने ईंधन के मूल्यों को डिरेगुलेट कर लोगों पर और भारी बोझ डाल दिया।

मुद्रास्फीति रोकने के लिए आपूर्ति संबंधी समस्या का समाधान करने के बजाय सरकार ने 17 बार ब्याज दरें बढ़ाकर निवेश एवं मांग को लगातार कम कर दिया। इसने खाद्य स्टॉक का कुप्रबंधन किया और इसे मार्किट में ना लाकर खुले में सड़ने दिया। एक विस्तृत रणनीति अपनाने में इनकी असफलता के परिणामवश: मूल्य लगातार बढ़ते रहे। सरकार दिशाहीन रही और यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी स्थिति में सुधार लाने में अपनी लाचारी दिखा दी। जब उन्होंने यह कहा "'पैसा पेड़ों पर नहीं उगता" "हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है।" सरकार ने अपनी विफलता भारतीय रिजर्व बैंक पर थोप देने की भी कोशिश की।

इससे आमजन को नुकसान हुआ और उनके जीवन स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ा। वास्तविक मजदूरी में कम हुई और कुपोषण बढ़ गया। गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर रहने वाले लोगों को गरीबी के जाल में धकेल दिया गया। वास्तविकता है कि मुद्रास्फीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वास्तविक परिसंपत्तियों का स्थानांतरण गरीब से गैर गरीब वर्ग की ओर होता है।

बेरोजगारी - एक भारी खतरा

बुनियादी ढांचे में ये सरकारी निवेश और निम्न ब्याज दर के कारण आवास, दूरसंचार एवं सिंचाई जैसे अन्य क्षेत्रों में निजी निवेश के बलबूते राजग अपने शासन काल में सफलतापूर्व 6 करोड़ 50 लाख रोजगार का सृजन कर पाया। उद्योगों का निर्यात बढ़ा और इस कारण रोजगार भी बढ़े।

यूपीए ने इस प्रक्रिया को बदल डाला और ब्याज की ऊंची दर आम बात हो गई। बुनियादी ढांचे में मंद विकास और अनिर्णय के कारण अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर ठप्प हो गये। राजग ने अपने छ: वर्ष के शासनकाल में जो हासिल करके दिखाए यूपीए अपने दस वर्ष के कार्यकाल में उसका अंशमात्र ही हासिल कर पायी। इसे इस परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है जब कि हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवा रोजगार क्षेत्र में अवसर हेतु प्रवेश करते हैं।

इससे भी अधिक चिंताजनक स्थिति यह है कि यूपीए शासनकाल के दौरान 2 करोड़ से अधिक रोजगार पर लगे लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। कपड़ा, डायमण्ड, सेवा क्षेत्र और अनेक लघु उद्योगों को छंटनी और तालबंदी का मुंह देखना पड़ा। पिछले 10 वर्षों में 25 प्रतिशत से अधिक छोटे और मंझोले उद्योग या तो बंद हो गये हैं या बंद होने के कगार पर है। इसके फलस्वरूप भारी पैमाने पर बेरोजगारी हुई है।

सरकार लगभग 500 मिलियन युवाओं के लिए 20 वर्ष की अवधि वाला एक महत्वाकांक्षी गुणवत्ता विकास कार्यक्रम बनाया परन्तु इसमें वह बुरी तरह असफल हुई। सरकार ने कार्यक्रम के शुरूआत से ही इसके गड़बड़ी की। जुलाई 2008 में उन्होंने कौशल विकास संबंधी प्रधानमंत्री की ''नेशनल कौन्सिल'' बनाई। इसी महीने उन्होंने राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय समिति बनायी। पूरे ढ़ाई वर्ष तक इस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। 2013 में भारत सरकार ने आदेश जारी किया, जिसके अन्तर्गत एक नई राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी बनाई गई। जिसमें पूर्व की तीनों एजेंसियों को समाविष्ट कर दिया गया। इसकी शुरूआत से अभी तक पांच साल गुजर गये हैं लेकिन इस संबंध में धरातल पर कुछ नहीं हुआ। कौशल बढ़ाने पर किये जाने वाले प्रधानमंत्री कौन्सिल का जिम्मा पहले उनके सलाहकारों के कार्यालय को और फिर एक ऐसी एजेंसी को सौंप दिया गया जिसके अध्यक्ष एक कैबिनेट मंत्री होंगे। उन्होंने अपेक्षित वैश्विक स्तर कौशल उपलब्ध न कराकर जनसांख्यिकीय आधार पर विश्व में उपलब्ध रोजगार के अवसरों को व्यर्थ जाने दिया। इस देश का युवा अपने लिए रोजगार के अवसर न सृजित कर पाने की इस यूपीए सरकार की विफलता को कभी माफ नहीं कर पायेगा।

भाजपा के पास अतीत में रोजगार के अवसर सृजित करने का रिकार्ड है वह रोजगार के रूप में युवाओं के लिए एक नयी पेशकश करेगा।

भाजपा के पास रोजगार के अवसर सृजित करने का रिकार्ड है वह रोजगार के रूप में युवाओं के लिए एक नया डील की पेशकश करेगा।

भ्रष्टाचार-एक असल यमदूत

यूपीए सरकार द्वारा किये गये भ्रष्टाचार का देश के कोर सेक्टरों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता। 2जी, 3जी, कोलगेट, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला और अन्य घोटालों में भारी लूटपाट के अलावा इनके घोटालों के कारण अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्र पंगु हो गये। भ्रष्टाचार का दुष्प्रभाव दो प्रकार से हुआ। एक सरकारी ख्जाने को

हुई अभूतपूर्व क्षति थी एवं वहीं दूसरी ओर बैंकों के डूबे कर्जे में हुई वृद्धि।

संचार क्षेत्र द्रुत गति से विकास कर रहा था और उसे अधिक से अधिक स्पेक्ट्रम की आवश्यकता थी। अगर सरकार स्पेक्ट्रम की बोली पारदर्शी प्रक्रिया से की गयी होती तो न केवल इस क्षेत्र का सुचारू विकास हुआ होता बल्कि देश को निविदा की रकम से भारी फायदा पहुंचता पर कांग्रेस ने इसकी बिक्री को अभूतपूर्व घोटाले में परिवर्तित कर दिया। 1.76 लाख करोड़ के इस घोटाले ने न केवल इस क्षेत्र का विकास रोक दिया बल्कि अब परिस्थिति ऐसी हो गयी है कि स्पेक्ट्रम के खरीददार सरकार पर से भरोसा उठ जाने की वजह से निविदा प्रक्रिया को संशय से देखते हैं।

खनन क्षेत्र भी पूरी तरह बर्बाद हो गया है इसके परिणामस्वरूप न केवल उत्पादन प्रभावित हुआ है बल्कि उद्योगों का भी चक्का जाम हो गया है।

कोयला जिसका असल में निर्यात किया जा सकता था अब वही कोयला ब्लाक आवंटन में हुए घोटाले परिणामवश के भारी मात्रा में आयात करना पड़ रहा है। यदि सरकार ने एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई होती यह तो उद्योग आज बर्बाद न हुआ होता।

वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले और अन्य रक्षा घोटालों के कारण न केवल हमारी छवि खराब हुई है अपितु इनके कारण हमारी रक्षा तैयारी भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। इटली जिसे इस सौदे से लाभ होना था, ने बिचौलियों और रिश्वत देने वालों को पकड़ कर उन पर मुकदमा चलाया। परन्तु भारत जिसे इस घोटाले से भारी नुकसान हुआ वह हमेशा कार्यवाही से बचता रहा। प्रमुख बिचौलिये क्रिश्चियन मिशैल से कोई पूछताछ नहीं की जा रही। दूसरे बिचौलिये हैश्चके एन गैरोसा ने रिश्वत लेने वाले राजनेताओं का नाम संक्षिप्त कर 'AP' और 'FAM' अपनी डायरी में लिखा है। संक्षिप्त नाम अपनी डायरी में लिखें। इटली की कोर्ट और वहां के अभियोजक ने 'AP' और 'FAM' नामों की पहचान के बारे में बिचौलियों से पूछताछ की परंतु सीबीआई ने इन जायज प्रश्नों को पूछना भी उचित नहीं समझा।

संकट में वित्तीय क्षेत्र

वित्तीय क्षेत्र कुछ गंभीर चिंताएं व्यक्त कर रहा है। बैंकिंग प्रणाली बढ़ती हुई गैर निष्पादित पूंजी के कारण संकट में हैं। यह पूंजी 1.5 लाख करोड़ बैठती है। अवरूद्ध ऋण और सीडीआरएस की मांग बढ़ती जा रही है। दूरसंचार क्षेत्र में अवरूद्ध कार्य दो लाख करोड़ के आसपास है और विद्युत क्षेत्र में यह लगभग 2.5 लाख करोड़ है।

इसके अलावा खनन, कपड़ा, नगर-विमानन और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में भी भारी मात्रा में ऋण बढ़ा है इसके कारण बैंकों के बैलेंस शीट बुरी तरह प्रभावित हुई है और वित्तीय क्षेत्र में भी इसका बहुत अधिक कुप्रभाव पड़ा है।

कर सुधार और काला धन

यूपीए सरकार की निष्क्रियता और राज्यों के सरकारों का समाधान करने में इसकी विफलता के कारण कर सुधार प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकी है। भाजपा कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाने और उसके सरलीकरण के लिए वचनबद्ध है।

कालाधन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बना हुआ है। यहां तक कि यूपीए सरकार ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध यूएन कन्वेंशन का समर्थन करने के बाद भी शेष औपचारिकताओं को अभी तक पूरा नहीं किया है। भाजपा ने श्री एल के आडवाणी के नेतृत्व में इसके विरूद्ध निकाली गई यात्रा के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया और इसे 2009 के चुनावों से ही इसे एक प्रमुख मुद्दा बनाया है। हम कालेधन के विरूद्ध अपने रूख को दोहराते हैं और इसे आवश्यक कानूनी एवं अन्य निर्णय प्रक्रिया के माध्यम से इसे वापस लाने का संकल्प करते हैं।

लकवाग्रस्त नीति

यूपीए सरकार लगातार अनिर्णय और नीतिपंगुता से ग्रस्त रही। लाखों करोड़ों की अनेकों परियोजनाएं स्वीकृति की प्रतीक्षा में लंबित पड़ी हुई हैं। अनेक अनावश्यक कारणों के कारण सैकड़ों प्रस्ताव पर्यावरण संबंधी अनुमति के लिए अटके हुए हैं। कई अन्य परियोजनायें अनेक प्रमुख कारणों जैसे कि एनएसी के हस्तक्षेप और सत्ता के वास्तविक केन्द्रों के हस्तक्षेप के कारण प्रधानमंत्री कार्यालय में अटकी हुई है। इसका परिणाम बहुत खतरनाक है। प्रधानमंत्री ने तेजी से इनका निपटारा करने के लिए ईजीओएम गठित किया फिर भी कोई वास्तविक प्रगति नहीं हुई। नीति पंगुता कांग्रेस राज का पर्याय बन चुकी है।

रूपये में भारी गिरावट

जब सरकारी तंत्र की निष्क्रियता के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ने से भारी वित्तीय घाटा हुआ। आयात बहुत अधिक बढ़ गये परंतु निर्यात में उसके अनुसार वृद्धि नहीं हो पाई, जिसके कारण चालू खातों में भारी घाटा हुआ और डॉलर तथा अन्य मुद्राओं के मुकाबले रूपये में भारी गिरावट आई। जब एनडीए ने शासन छोड़ा तो रूपये की कीमत प्रति यूएस डॉलर के मुकाबले 45 रू था और अब 62 से 65 रूपये के बीच है। यूपीए शासन काल में रूपये का 40 प्रतिशत अवमूल्यन हुआ।

सरकार ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि ''यूएसफेड'' द्वारा ''क्वांटीटेटिव इजींग'' की घोषणा के बाद सभी मुद्रायें प्रभावित हुई हैं परंतु वास्तविक तथ्य कुछ और ही थे। विश्व में किसी भी अन्य उभरती अर्थव्यवस्था को ऐसी बुरी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा जैसा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में देखा गया।

देश को रूपये की कीमत में आई भारी गिरावट के कारण अनेक खतरनाक परिणाम भोगने पड़े। आयात महंगे होते गए, जिसके कारण मुद्रास्फीति अप्रत्याशित ऊंचाई पर पहुंच गई तथा

विदेशी शिक्षा भी महंगी हो गई। किसी को भी नहीं पता कि वास्तविक स्थिरता कब लौटेगी क्योंकि आज भारतीय रिजर्व बैंक तेल निर्यात के लिए सीधे विदेशी मुद्रा जारी कर और सोने पर कस्टम ड्यूटी में अतिशय वृद्धि करके रूपये को सम्भालने का प्रयास कर रहा है, जिसकी वजह से हवाला दिनों की वापसी का खतरा बन गया है।

किसानों और श्रमिकों की अनदेखी

वर्तमान सरकार ने किसानों और श्रमिकों की जबरदस्त अनदेखी की है। इसने किसानों को वास्तविक लाभप्रद मूल्य तो नहीं ही दिये साथ ही स्वामीनाथन फार्मूले की लाभप्रद मूल्यों की सिफारिश को स्वीकार करने से हमेशा ही इन्कार किया है। यूपीए शेखी बघारती है कि इसने राजग सरकार की तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य में उससे ज्यादा वृद्धि की है परंतु उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि उसके काल में वास्तविक लागत मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि की तुलना में ज्यादा बढ़ी है। उर्वरकों, कीटनाशकों, बीजों और सभी इनपुट सामग्री की लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

यूपीए शासनकाल के दौरान वर्ष दर वर्ष कम होते गये उनके मुनाफे के निम्नलिखित ताजा आंकड़े किसानों के प्रति हुए अन्याय को साबित करते हैं।

सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र इस समय बुरी तरह से त्रस्त है तथा इसमें तुरंत सुधार किए जाने की आवश्यकता है। किसानों द्वारा आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या, बढ़ते हुए ऋण, .षि से पलायन आदि इसके गिरावट के संकेत हैं। सिंचाई में सरकारी निवेश आवश्यकता की तुलना में कम है अत: यूपीए शासनकाल अपने कार्यों और नीतियों के कारण न केवल किसान विरोधी, श्रमिक विरोधी साबित हुई बल्कि अनुसूचित जाति, जनजातियों और समाज के अन्य वंचित वर्गों के हितों के विरूद्ध भी साबित हुआ। छोटे और मझौले उद्योगों, लघु उद्योगों और कारीगरों को संरक्षण देने की अत्यावश्यक जरूरत है।

बाली में समर्पण

भारत सरकार ने बाली में विश्व व्यापार संगठन की 9वीं मंत्री स्तर की कान्फ्रेंस में ट्रेड फेसिलेटेशन को मानकर देश के आर्थिक हितों के साथ समझौता किया है। यह बड़ी विचित्र बात है क्योंकि भारत 2001 से ही ट्रेड फेसिलेटेशन का दृढ़ता से विरोध करता आ रहा है। यह चार सिंगापुर मुद्दों में से एक मुद्दा था जिन्हें अकेले भारत के विरोध के कारण निरस्त कर दिया गया था। भारत ने एक पीस क्लॉज पाने के लिए वृहत्तर बाजार उपलब्धता देने को दुर्बलतापूर्वक तैयार हो गया। इसके परिणामस्वरूप खाद्य सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के अंतर्गत आ गई और इसके विस्तार पर अनेक बाधाएं लग गई। यहां तक कि भारत बाह्य मूल्य सूचकांक में सुधार कर पाने में भी असफल रहा जिससे भारत को न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य कारकों के परिप्रेक्ष्य में एक उपाय मिल जाता।

गरीबों का मजाक

सरकार का पक्षपाती रवैया उस समय नजर आया जब उसने गरीबी रेखा को प्रतिदिन 32 रूपए के हिसाब से परिभाषित किया। गरीबी पर आई विभिन्न रिपोर्टों से यह भ्रम और भी बढ़ गया। प्रतिदिन 33 रूपए की आय वाले व्यक्ति को सरकार द्वारा गरीब न मानने के सरकार की इस नीयत के खिलाफ देश में आक्रोश व्याप्त हो गया। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार को फटकार लगाई। ऐसी परिस्थिति का कारण सरकार की सोच प्रक्रिया में व्याप्त भ्रम है।

सरकारी आंकड़ों पर प्रश्न चिह्न

पहली बार सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न लगाया जा रहा है। हाल ही में सरकार ने 2011-12 के सकल घरेलू उत्पाद विकास के बारे में अपने आंकड़ों में परिवर्तन कर दिया। सही आंकलन अच्छी योजना की नीवं होती है। आंकड़ों में तोड़-मरोड़ करना एक गंभीर कमी है और इसे पूरी गंभीरता के साथ दूर किया जाना चाहिए।

बुनियादी ढांचा विकास - राजग बनाम संप्रग

किसी प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बुनियादी ढांचा एक महत्वपूर्ण बात होती है। एनडीए ने सड़कों, राजमार्गों, रेलवे, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और सिंचाई बुनियादी ढांचों में परियोजनायें शुरू की थीं। इन परियोजनाओं ने दूर देहात का स्वरूप बदल दिया और भारी मात्रा में रोजगार के अवसर भी सुनिश्चित किये। सर्वशिक्षा अभियान, आई.टी. आदि के माध्यम से शिक्षा के विस्तार के लिए एनडीए द्वारा की गई पहल से राष्ट्रीय सम्पदा में वास्तविक वृद्धि हुई। जहां एनडीए ने प्रतिदिन 11 कि.मी. सड़क बनाने का लक्ष्य किया वहां यूपीए ने इसे दुगुना करके 22 किमी करने का वादा किया और वास्तविकता में 2 किमी

धान	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
किसानों का लागत मूल्य	742	888	1152
न्यूनतम समर्थन मूल्य	1000	1080	1250
लाभांश	34.77 %	21.62 %	8.5 %
गेहू	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
किसानों का लागत मूल्य	826	927	1128
न्यूनतम समर्थन मूल्य	1100	1120	1285
लाभांश	33.17 %	20.81 %	13.91 %

आंकड़े : कृषि लागत और मूल्य आयोग राज्यसभा के 227वें सत्र में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 105 उत्तर से

प्रतिदिन से भी कम का निर्माण किया। विद्युत अधिनियम 2003 देश ने विद्युत परिदृश्य में बदलाव किया और निर्बाध वृद्धि करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराये। यूपीए ने इस अवसर को भी खो दिया और अपने लक्ष्यों से भी कम उपलब्धि हासिल की। बड़े ताप विद्युत परियोजनाओं के विषय और निर्बाध कोयला आपूर्ति पर भी निष्फल रही। प्रधानमंत्री ने समूचे देश को जोड़ने वाली दो फ्रेट कोरिडोर की नींव रखी परन्तु आठ वर्ष की लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई इन पर नहीं हुई है। बुनियादी ढांचे की की गई अनदेखी से अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में और भी कमी आई है।

निवेशकों का विश्वास

यूपीए सरकार द्वारा भूतकालिक प्रभाव वाले कर प्रस्तावों और निवेश नीतियों में असंगत परिवर्तन से भारतीय और विदेशी निवेशकों के विश्वास को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया है। इसके परिणामस्वरूप इस समय भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इन पत्रों की तुलना में भारतीय बाहर अधिक निवेश कर रहे हैं। घोषित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फलीभूत नहीं हुए और पूर्व के निवेशों की वापसी बढ़ रही है इसमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

वर्तमान राष्ट्रीय चेतना

राष्ट्र इससे बेहतर परिस्थिति का अधिकारी है। आज जनता चाहती है कि देश सम्पूर्ण विकास के रास्ते पर तेजी से चले और पूर्ण रोजगार के अवसर और निरंतर बढ़ती हुई कीमतों और भ्रष्टाचार से मुक्ति सुनिश्चित हो। भाजपा यूपीए द्वारा भंवर में डाली गयी देश की अर्थव्यवस्था को उबार अभिनव प्रयासों से एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। भाजपा शासित राज्यों ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किस प्रकार आर्थिक विकास संभव हो सकता है। भाजपा के पास तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ और टिकाऊ आर्थिक विकास की एक स्पष्ट सोच है। यह श्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व के अंतर्गत एनडीए शासनकाल में देखा भलीभांति देश ने देखा। इस समय भारत को अर्थव्यवस्था को पुन: पटरी पर लाने के लिए वास्तविक राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था के मूल्य पर देश अब और नये राजनीतिक प्रयोग सहन नहीं कर सकता जिसके कारण देश को कांग्रेसनीत यूपीए शासनकाल के दौरान भारी नुकसान उठाना पड़ा। अत: भाजपा ने श्री नरेन्द्र मोदी के रूप में एक निर्णायक और प्रगतिशील नेता राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया है। देश के लोगों ने भाजपा के अभियान को भारी समर्थन व्यक्त किया है। मतदाता न केवल परिवर्तन के लिए मतदान कर रहे हैं अपितु वह एक निर्णायक जनादेश देने के लिए मतदान कर रहे हैं जो भारत के आर्थिक विकास के स्वरूप को बदल सकता है। लोग अब देश और इसके आर्थिक पुनरूत्थान के लिए मतदान कर रहे हैं। ■

पृष्ठ 23 का शेष...

अब देश को जगाने और निर्णायक बदलाव की उम्मीद पैदा करने का वक्त आ गया है। इस तरह का बदलाव सिर्फ भाजपा के उदय और सुशासन, सत्यनिष्ठा रिकार्ड और श्री नरेंद्र मोदी का निर्णायक नेतृत्व ही ला सकता है। स्वाभाविक है कि जिन्होंने पिछले कई वर्षों में कांग्रेस को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन दिया और जिन्होंने कांग्रेस की भ्रष्ट बैसाखी के जरिये सत्ता प्राप्त की है, जिसके वे घोर विरोधी रहे हैं, ऐसे सभी दल कांग्रेस के कुशासन का विकल्प नहीं हो सकते। राष्ट्र ''कांग्रेस मुक्त भारत चाहता'' है।

कांग्रेस की विरासत- नीतिगत पंगुता, नेतृत्व का अभाव, विकास का अभाव, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असुरक्षित भारत जहां सशस्त्र बलों का मनोबल भी नीचा है और हथियार और शस्त्र आपूर्ति भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है। परन्तु भाजपा का वादा - सशक्त नेता के साथ एक निर्णायक सरकार के जरिये देश की समस्याओं का समाधान करना और सुशासन तथा जवाबदेह सरकार के जरिये गरीब मजदूर, किसान, निम्न मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, युवा, महिला वर्ग, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सहित अन्य सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों के विकास का वादा।

भाजपा को वोट देने के लिए देश से अपील

भाजपा भारत के लोगों को आश्वस्त करना चाहती है कि हमारा नारा- ''इंडिया फर्स्ट'' है - भारत को उसका गौरवपूर्ण दर्जा दिलाने की प्रतिबद्धता - एक भारत जहां आशा हो - एक ऐसा भारत जो कि सुरक्षित है - एक ऐसा भारत जहां समानता के साथ विकास है और जिसमें सबका साथ है और जो समावेशी है। यह तभी संभव है जब ऐसी सरकार हो जो कि सुशासन दे सके और चहुंमुखी विकास सुनिश्चित कर सके। इसलिए हमारा ध्येय 272+ का है ताकि भारत को एक स्थाई सरकार मिले जो कि इस महान देश को उचित स्थान दिलाये जो भारतीयों का सपना है। श्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में विभिन्न जगहों पर भाजपा को जो समर्थन मिल रहा है वह देश की बदलाव की आकांक्षा का संकेत है।

राष्ट्रीय परिषद सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान करती है कि वे इंडिया फर्स्ट के ध्येय को पूरा करने के लिए खुद को समर्पित करें और देश के हर हिस्से में जायें, प्रत्येक परिवार से संपर्क करें और निर्णायक बदलाव के लिए प्रत्येक भारतीय को जागरुक करें। इसके लिए राष्ट्रीय परिषद विनम्रता के साथ देश की जनता से अपील करती है कि वह एक बेहतर और होनहार भारत के लिए भाजपा को निर्णायक जनादेश दे।■

आपने शासकों को 60 साल दिए, हमें 60 महीने दीजिए : नरेंद्र मोदी

देश की जनता से 60 महीने के लिए सेवा का मौका मांगते हुए भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। श्री मोदी बोले कि कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने श्री राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इसलिए नहीं बनने दिया क्योंकि मां के रूप में वह अपने बेटे की 'राजनीतिक बलि' के लिए तैयार नहीं थीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इसलिए घोषित नहीं किया क्योंकि इस कुलीन वर्ग को उन जैसे पिछड़ी जाति और चाय बेचने वाले के सामने मैदान में उतरने में शर्म महसूस होती है।

गत 19 जनवरी को भाजपा की दो दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा, ''राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाये जाने के मुझे दो कारण दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक कारण तो है ही लेकिन इसके साथ एक मानवीय कारण भी है। जब लोकसभा चुनाव में पराजय निश्चित दिख रही है और विनाश सामने नजर आ रहा है तो कोई मां अपने बेटे की राजनीतिक बलि चढाने के लिए तैयार नहीं होती है। तो मां का यही निर्णय रहा.. मेरे बेटे को बचाओ।''

उन्होंने कहा कि श्री राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाने के पीछे एक कारण यह भी है क्योंकि वह उच्च कुल में पैदा हुए हैं और कुलीन लोगों में एक भय यह भी है कि उनके सामने जो उम्मीदवार है, वह पिछड़ी जाति में पैदा हुआ है। श्री मोदी ने कहा, ''प्रधानमंत्री पद की दौड़ से भागने का और भी कारण है, वह यह कि जिस परंपरा में वह पले बढ़े हैं और जिस परिवार के हैं और जिस तरह वह जीते हैं, उनके मन की रचना भी सामंतशाही होती है। वह किसी चाय वाले से भिड़ना पसंद नहीं करेंगे।'' उन्होंने कटाक्ष किया, ''वे नामदार हैं, मैं कामदार हूं। ऊंच-नीच का मामला है।''

कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किये जाने की 'परंपरा' की दलील की चीर-फाड़ करते हुए श्री मोदी ने सवाल किया कि 1947 में भारत जब आजाद हुआ तो कांग्रेस की यह कथित परंपरा कहां चली गयी थी ? उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस एक स्वर में सरदार वल्लभभाई पटेल को प्रधानमंत्री चाहती थी लेकिन वो कौन सी परंपरा थी, जिसने पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया।

श्री मोदी ने कहा कि 1984 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो राजीव गांधी दिल्ली से बाहर कोलकाता में थे। वह तुरंत दिल्ली आये और कुछ ही पल में उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी गयी। उन्होंने कहा, ''परंपरा की बात करने वाली कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई संसदीय दल की बैठक हुई थी? क्या संसदीय दल ने प्रधानमंत्री चुना था? दो चार लोगों ने हड़बड़ी में उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर डाला और आज हमें परंपरा की सीख दी जा रही है।''

उन्होंने कहा कि 2004 के लोकसभा चुनाव के बारे में भी ''मैं दावे से कह सकता हूं कि किसी संसदीय दल ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नहीं चुना था। उसने सोनिया गांधी को इस पद के लिए चुना था लेकिन बाद में सोनिया जी

ने मनमोहन जी को मनोनीत कर उन्हें इस पद पर नियुक्त कर दिया। संसदीय परंपरा की बातें करके कांग्रेस के नेता सच्चाई से नहीं बच सकते।''

कांग्रेस के एक नेता द्वारा उन्हें 'चाय वाला' कहे जाने पर व्यंग्य करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन दिनों चाय वाले की बड़ी खातिरदारी हो रही है। देश का हर चाय वाला आज सीना तान कर घूम रहा है। चाय वाले से भिड़ने में कांग्रेस को बडी शर्मिन्दगी हो रही है। ये बहुत ईमानदार है (लोग कहते हैं)। उन्हें (कांग्रेस को) ईमानदार से मुकाबला करने में शर्म महसूस होती है। कांग्रेसियों के मेरे बारे में ऐसे बयान उनकी सामंतवादी मानसिकता को दर्शाते हैं।

कांग्रेस नेताओं पर हमला जारी रखते हुए श्री मोदी ने कहा कि 'टेप रिकार्ड' पर भरोसा करें या 'ट्रैक रिकार्ड' पर। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण देश की हालत खराब है। देश की समस्याओं की जड़ में कुशासन है। सिर्फ 'बिल' (विधेयक) नहीं बल्कि राजनीतिक 'विल' (इच्छाशक्ति) चाहिए और उन्हें लागू करने के लिए 'दिल' चाहिए। ''बिल बिल हम बहुत सुन चुके, अब एक्ट 'कानून' नहीं एक्शन चाहिए।''

केंद्र और राज्यों के परस्पर मिलजुल कर कार्य करने की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मिलकर काम करने की जरुरत है। साथ ही कहा कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संकट नहीं समझना चाहिए बल्कि उसे विकास का अवसर मानना चाहिए। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को चुनौती नहीं मानना चाहिए बल्कि उसकी इज्जत करनी चाहिए।

श्री मोदी ने कहा कि गुजरात का कई वर्षों से मुख्यमंत्री होने के नाते संघीय ढांचे का क्या महत्व है, वह बखूबी समझते हैं। हर राज्य का महत्व और उसकी पीड़ा को वह भलीभांति समझ सकते हैं इसलिए सरकार बनने पर भाजपा संघीय ढांचे को शक्तिशाली बनाने में रुचि दिखाएगी। उन्होंने कहा कि भारत का विकास समान रुप से नहीं हुआ है।

इसमें क्या कमी और क्या खोट रह गयी, उसे हम देखेंगे और दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में कुछ विकास नजर आ रही है लेकिन क्या कारण है कि मध्य से पूरा पूर्वी भारत विकास के लिए तड़प रहा है। ''ये असंतुलन क्यों है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर मुझे सेवा का अवसर मिला तो पहली गारंटी भारत के वो इलाके जो पिछड गये हैं, उन्हें सबसे पहले आगे बढाने का काम शुरु होगा।''

संप्रग सरकार पर निशाना साधते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश ने पिछले एक दशक में जितने बुरे दिन देखे, उतने कभी नहीं देखे। भ्रष्टाचार और महंगाई चरम पर है और हर तरफ गरीबी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल देश पर शासन किया है और अब समय आ गया है कि भाजपा को 60 महीने के लिए काम करने का मौका दिया जाए। ''60 साल आपने शासक चुने .। मैं जनता से अपील करता हूं कि आपने शासकों को 60 साल दिये, अब इस सेवक को 60 महीने दीजिए। अब सेवक का समय आ गया है।'' श्री मोदी ने कहा कि, ''हमारे विचार राष्ट्रवादी हैं और उनके (कांग्रेस के) विचार वंशवादी।''

उन्होंने श्री राहुल गांधी की इस टिप्पणी के लिए भी उन पर प्रहार किया कि टिकट उन्हीं को दिया जाएगा, जिनके दिल में कांग्रेस है। ''हमारी सोच है कि टिकट उन्हीं लोगों को दिया जाना चाहिए, जिनके दिल में देश है।'' श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र अब तक प्रतिनिधि वाला रहा लेकिन अब समय आ गया है कि शासन में लोगों को अधिक से अधिक शामिल कर इसे जन भागीदारी वाला बनाया जाए। ■

विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ भाजपा के अध्यक्ष बने

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं रायगढ़ के सांसद श्री विष्णुदेव साय को 21 जनवरी 2014 को छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया। श्री साय दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे।

विनोद पांडे बने झारखंड प्रदेश भाजपा के प्रभारी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने 21 जनवरी 2014 को पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री विनोद पांडेय को झारखंड प्रदेश भाजपा का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया। श्री पांडेय भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। वे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं।